come-tax (Fourth Amendment) Rules, 1964, under section 296 of the Income-tax Act, 1961. [Placed in Library. *See* No. LT-3464/64].

THE LIFE INSURANCE CORPORATION (AMENDMENT) RULES, 1964

SHRI RAMESHWAR SAHU: Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification G.S.R. No. 1568, dated the 23rd October, 1964, publishing the Life Insurance Corporation (Amendment) Rules, 1964, under sub-section (3) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956. [Placed in Library. *See* No. LT-3405/64].

THE CENTRAL SALES TAX (REGISTRATION AND TURNOVER) AMENDMENT RULES, 1964

SHRI RAMESHWAR SAHU: Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Company Law), Notification G.S.R. No. 1584, dated the 26th October, 1964, publishing the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Amendment Rules, 1964, under sub-section (2) of section 13 of the Sales Tax Act, 1956. [Placed in Library. *See* No. LT-3465/64].

THE BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 1964—*continued.*

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) : सभापति जी, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह "बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक" है। बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी में गत कुछ समय से जो दुर्घटनायें घटी हैं, झगड़े हुए हैं और अव्यवस्था फैली है, उन सबको देखकर हमारा शासन चाहता है कि वहां की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया जाये। वहां पर अधिकारियों को जो अधिकार दे रखे हैं, उन्हें और बढ़ा दिया जाये जिससे कि वहां की व्यवस्था ठीक हो सके।

[THE DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*]

वहां पर जो गड़बड़ी हुई, जो सारी अव्यवस्था हुई, उसके बारे में हमारे पूर्ववक्ता श्री चन्द्र शेखर जी ने खास तौर पर विस्तार से प्रकाश डाल दिया है और मैं उन बातों को यहां पर दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन जहां तक इस बिल का सवाल है, उसके अन्तर्गत खंड ५ (डी) में जो संशोधन चाहा गया है, उसके द्वारा वेतन पाने वाले अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों को अध्यादेश द्वारा अनुशासन में रहना होगा। इसमें अभी तक अनुशासन की जो बात थी, जो बंधन था, वह केवल विद्यार्थियों के लिए ही सीमित था। परन्तु इस धारा के अन्तर्गत सरकार यह चाहती है कि अधिकारी भी अनुशासनबद्ध रहें। उसमें ये शब्द हैं :

"(12A) to regulate and enforce discipline among salaried officers, teachers and other employees of the University in accordance with the Ordinances;".

यह बिल्कुल सही बात है; क्योंकि हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे यहां नैतिक बंधन बढ़ता जाये, अध्यापक भी इतने अच्छे रहें, वे दूसरों के लिए एक आदर्शस्वरूप हों, जैसे कि हम प्राचीन काल में कल्पना करते थे और उस समय गुरु और शिष्य का जो संबंध था, वही हम चाहते हैं। लेकिन जब हमने यहां पर चित्रपट में "प्रोफेसर" नाम का फिल्म देखा, जिसमें प्रोफेसर और विद्यार्थियों के जीवन का दिग्दर्शन करवाया गया था, जिसे सेन्सर बोर्ड ने भी पास कर दिया था, उसी तरह का जीवन देश में प्रोफेसरों का बनता जा रहा है। जिस तरह का प्रदर्शन उस चित्र में किया गया था, उसको देखकर ऐसा लगता है कि हमारे देश में उच्छृंखलता, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता, जो अभी तक केवल विद्यार्थियों तक ही फैली थी, यह बीमारी दुर्भाग्य

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया]

से सैलरीड स्टाफ पर भी फैल चुकी है और उसका रोकना अत्यन्त आवश्यक है। इस दृष्टि से इसमें जो संशोधन चाहा गया है, वह सचमुच में बहुत ही अच्छा है।

परन्तु, हमें इस संशोधन के साथ ही साथ इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिये और इस बात की गहराई पर जाना चाहिये कि विद्यार्थियों और अध्यापकों के व्यवहार में जो परिवर्तन आ गया है, इतने झगड़े हुए हैं, इतनी अनुशासनहीनता होती जा रही है, इतनी सारी अव्यवस्था होती जा रही है, उसका कारण क्या है? अगर हम इन कारणों को देखेंगे और जब हम यह चाहते हैं कि व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिये, अच्छी अच्छी बातें होनी चाहियें, सत्य का आचरण करने को कहते हैं, अनुशासन में रहने के लिये कहते हैं तो हमें यह देखना होगा कि अध्यापक का व्यवहार कैसा है। जो पढ़ाने वाले हैं, अगर उनमें ही अनुशासन-हीनता हो जाती है जब कि वे चाहते हैं कि हमारा एक स्तर होना चाहिये, ताकि हम एक अमुक आदर्श जीवन व्यतीत कर सकें, तो यह स्वाभाविक है कि विद्यार्थियों पर भी इसका असर होता है। कई छोटे छोटे स्कूलों और कालेजों में ऐसी-ऐसी स्थिति होती है कि अध्यापक लड़कों से यह कहते हैं कि जा करके सिग्रेट पिलाओ, सिग्रेट खरीद लाओ, आदि, आदि। यह किसी के लिए खराब हो सकता है और किसी के लिये अच्छा हो सकता है। पर मैं तो इस मत का हूं कि ये छोटी छोटी बातें ही, जैसे सिग्रेट लाना, लड़कों के सामने अभद्र व्यवहार करना, मज़ाक करना और इसी तरह का जो निम्न स्तर का व्यवहार हो सकता है, वह करना, इसी के परिणामस्वरूप जो हम अनुशासन चाहते हैं, वह हो नहीं पाता और इसी कारण विद्यार्थियों की बीमारी अधिकारियों और अध्यापकों पर भी पड़ी और अब हम उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं और यह प्रतिबन्ध एक क्यूरेटिव मेज़र होगा। मगर हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षा-मंत्री जी, जो बहुत बुद्धिमान् हैं और बहुत सोच-समझ कर काम करते हैं, वे इसमें भी ज़रा गहराई से सोच कर इसका कोई प्रिवेंटिव मेज़र निकालेंगे, जिसके आधार पर इस तरह की जो बीमारी हमारे देश में बढ़ती जा रही है, उस पर रोक लग सके। इस वक्त अगर यह सब देखना हो तो वह "प्रोफेसर" का जो चित्रपट है, उसमें देखिये। यह चित्रपट मैंने स्वयं नहीं देखा है, लेकिन सुने-सुनाये के आधार पर कहता हूं कि उसमें प्रोफेसर का जीवन कैसा उच्छृंखल है, और किस तरह की छात्र और छात्राओं की हालत है, यह सब उसमें बताया है। ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड ने जब उसको इजाज़त दी तो यह समझ कर दी कि हमारे देश में इस तरह की उच्छृंखलता बढ़ती जा रही है और इसीलिये इस तरह का चित्रपट चले तो कोई आपत्ति नहीं है। तो यह जो उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता और अव्यवस्था बढ़ती जा रही है, इसका क्यूरेटिव मेज़र करने के साथ साथ प्रिवेंटिव मेज़र की बात भी आप सोचें और उसके ऊपर गहराई से विचार करें तो अधिक अच्छा होगा।

दूसरे ५ (एफ) में १३ (बी) द्वारा संशोधन चाहा गया है और उसमें कर्ज़ लेने का अधिकार दिया जा रहा है, किन्तु उसकी स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से लेनी होगी। अब एक ओर तो हम यह कहते हैं कि उस विश्वविद्यालय की कोर्ट ही सुप्रीम अथारिटी होगी और वह जो कुछ निर्णय लेगी, जो कुछ तय करेगी, वह फाइनल होगा और उसको हर प्रकार की व्यवस्था करने का पूरा अधिकार होगा। मगर इस क्लाज़ में हम यह बंधन लगा रहे हैं कि अगर कुछ भी कर्ज़ लेना हो तो उसकी केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। इस तरह धारा १३ (बी) द्वारा जो

संशोधन चाहा गया है, उसमें कुछ तुक ठीक लगता नहीं और यह व्यवस्था कुछ ठीक है, ऐसा लगता नहीं । अगर कुछ बंधन ही लगाना हो तो आप ऐसा कीजिये कि कुछ लिमिट्स बना दीजिये कि इतनी लिमिट में कर्ज़ लेना होगा तो इस अधिकारी की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, इतनी सीमा तक कर्ज़ लेना होगा, तो रेक्टर की स्वीकृति से काम चलेगा और इतना कर्ज़ लेना होगा तो कोर्ट की स्वीकृति से काम चल सकेगा और उससे अधिक कर्ज़ लेना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वीकृति लेनी पड़ेगी । मगर हर कर्ज़ के बारे में इसमें यह बंधन लगा देना कि कोई भी कर्ज़ लेना हो तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वीकृति से ही लिया जा सकता है, यह ठीक लगता नहीं । इस प्रकार यदि छोटे-छोटे कामों में भी दखल दिया जायेगा तो उनको बड़ी कठिनाई होगी और इस कठिनाई से उनको मुक्ति देने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था करें कि इतनी लिमिट तक कर्ज़ लिया जायेगा तो उसके लिये रेक्टर की स्वीकृति की आवश्यकता होगी, इतनी लिमिट तक कर्ज़ लिया जायेगा तो उसके लिये कोर्ट की स्वीकृति की आवश्यकता होगी और उससे ज्यादा कर्ज़ लेना होगा तो उसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वीकृति लेनी पड़ेगी । तो यह जब तक हम नहीं करते तब तक हम उस यूनीवर्सिटी में ठीक व्यवस्था नहीं कर सकते, ऐसा मुझे प्रतीत होता है ।

चांसलर और प्रोचांसलर साहब के कार्यकाल की अवधि तीन साल रखी गई है और उसमें समय पूरा हो जाने पर नये चुनाव तक उनको उसी पद पर काम करते रहना पड़ेगा । मैं यह नहीं जानता कि यहां पर क्या स्थिति होती है । मगर मैं जब एक छोटी सी नगरपालिका का उदाहरण देखता हूं, जिसमें यह प्रावधान रहता है कि उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों की कालावधि तीन वर्ष रहेगी, किन्तु वे नये चुनावों तक काम करते रहेंगे, उसका परिणाम यह होता है कि उस नगरपालिका के सदस्य नये चुनावों को आने नहीं देते और उनको टालते रहते हैं और इस प्रकार कभी कभी उनकी अवधि एक-एक, दो-दो और तीन-तीन वर्ष तक बढ़ जाती है । मैं नहीं समझता कि यहां पर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें हम ऐसा स्पष्ट प्राविज़न ही क्यों न कर दें कि इतनी अवधि के अन्दर नये चुनाव निश्चित रूप से हो जायें और न होने की स्थिति में रेक्टर साहब या कोर्ट जिसको चाहे उसको अधिकार दे कर वहां का काम चलवाये ? इसके अभाव में ऐसा हो सकता है कि उसमें वेस्टेड इंट्रेस्ट होने के परिणामस्वरूप तीन साल की अवधि हो जाने के बाद भी वे अपने पदों पर काम करते रहें और नये चुनावों को टालने का प्रयत्न करते रहें । इसलिये इस ओर ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगा दिया जाये जिससे समय से नये चुनाव हो जायें ।

अब वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिये जो इसमें व्यवस्था की गई है, उसमें यह है कि एक समिति बनेगी और उस समिति के दो सदस्य एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल नियुक्त करेगी और एक सदस्य विज़िटर नियुक्त करेंगे और वह समिति तीन आदमियों का पैनल बना कर भेजेगी और उस पैनल में विज़िटर जिसको चाहेगा उसको नियुक्त करेगा और नहीं चाहेगा तो वह फिर उस पैनल को वापस कर सकता है और यह कह सकता है कि फिर तीन नाम भेजो । इस तरह उस आटोनामस बाडी को आप पूरा अधिकार दे रहे हैं, ऐसा कुछ लगता नहीं । वास्तव में यह होना चाहिये कि हमको कोर्ट पर यह छोड़ देना चाहिये कि वह किसको वाइस-चांसलर रखना चाहती है और किस को नहीं रखना चाहती है । उस समिति में इतना होने के बावजूद कि उसके तीन सदस्यों में से एक सदस्य स्वयं विज़िटर द्वारा नामिनेट किया हुआ होगा, फिर भी विज़िटर को

[श्री विमल कुमार मन्नालालजी चोरड़िया]

यह अधिकार दिया जा रहा है कि उसकी मर्जी हो तो उन तीन नामों में से किसी को माने और न मर्जी हो तो उसको वापस कर दे और कहे कि फिर नाम भेजो । यह कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता और इस बारे में कुछ विचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

दूसरे ७ डी (४) के द्वारा वाइस-चांसलर की जो अवधि पांच साल की है, उसके बाद वह दूसरे टर्म के लिये भी नियुक्त किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में धारा इस तरह से है :

"The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall at the expiry of such term be eligible for re-appointment for a second term."

अब एक तो यह प्रश्न आता है कि क्या हम उसको केवल सैकेंड टर्म के लिये ही रखना चाहते हैं और क्या वह तीसरे टर्म के लिये फिर से अप्वाइंट नहीं हो सकता; क्योंकि जब हम इसमें "सैकंड टर्म" शब्द लाते हैं तो उसमें यह व्यवस्था इम्प्लायड हो जाती है कि हम उसको थर्ड टर्म के लिये नहीं चुनना चाहते है । अगर हम फिर से उसके रिएलेक्शन या रिअप्वाइंटमेंट की व्यवस्था करते तो यह क्लाज़ हम यहीं तक खत्म कर सकते थे :

"The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall at the expiry of such term be eligible for re-appointment . . ."

तो यहीं तक रख कर इसको समाप्त किया जा सकता था, लेकिन जब इसमें यह भी रखा गया है : "re-appointment for a second term" इससे हम एक बन्धन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें लगा देते हैं कि सैकंड टर्म के बाद वह थर्ड टर्म के लिये रिअप्वाइंट नहीं हो सकता । तो लक्ष्य क्या है, बताने का कष्ट करें ।

SHRI NAFISUL HASAN (Uttar Pradesh): That is what is intended.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया : जो भी इंटेंशन हो, मैं तो यही समझता हूं कि इसका यही मतलब है जो कि मैं बतला रहा हूं और इसलिये इन शब्दों को इसमें नहीं रखना चाहिये । यूनीवर्सिटी कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसमें इसके बारे में बड़ा स्पष्ट दिया है और मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं । हमारे शिक्षा-मंत्री अक्सर जब कुछ कहना चाहते हैं तो यह कह देते हैं कि फलां कौंसिल ने यह कहा, फलां कमेटी ने यह कहा और मैं तो केवल एक्ज़ीक्यूट करने वाला हूं । इसलिये मैं उनसे यह निवेदन करता हूं कि वे इस पर भी विचार कर लें जो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पेज ४२३ पर बताया है । वह इस प्रकार है :

"Practically all our witnesses agree that a full-time, paid Vice-Chancellor needs a longer tenure of office than has been the custom hitherto. He will not be able to play his full part as we have tried to describe it until he has made himself known and trusted both in and outside the university. Many of our witnesses have suggested that he should be appointed for five years and should be eligible for re-election. We feel however that to require or to allow re-election is unwise . . .

"We have had deplorable evidence that from the day of his appointment a Vice-Chancellor's every decision is liable to be swayed by his need to secure votes for his re-election, and that he may refuse to take quite necessary action for fear of consequent unpopularity. Even where this is not the case,

the suspicion that it may be the case does almost equal harm. We believe that our proposals will go far towards eliminating the appointment of such weak Vice-Chancellors, but still we think it unfair to subject them to this difficulty. The simplest way of avoiding re-election would be to make his tenure of office indefinite, as in U.S.A. or subject only to the same retiring age as professors, as in the unitary universities of Great Britain. Some of us believe that this is the ideal plan, but yield reluctantly to the opinion of our majority that this involves a more drastic change from present practice than it would be wise to commend. We therefore unanimously recommend that all Vice-Chancellors should be appointed for six years and should not be eligible for re-election."

तो ऐसी स्थिति में उसका रिएलेक्शन हो या रिअप्वाइंटमेंट हो, उसके बारे में जो शंकाएं कमीशन ने, आयोग ने व्यक्त की हैं वे बिल्कुल सही हैं । विश्वविद्यालय सरीखे स्थान पर ऐसी शंकाओं का पैदा भी होने देना ठीक नहीं है । न्याय तो होना ही चाहिए, बल्कि यह भी आवश्यक है कि न्याय हुआ है, ऐसा दिखाई पड़े, ऐसा भी होना चाहिए । ऐसी स्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम रिअप्वाइंटमेंट के प्रश्न पर पुनर्विचार करें । अगर हम अधिक समय देना चाहते हों तो विचार करके थोड़ा अधिक समय दे दें, लेकिन छः साल की बजाय पांच साल कर के फिर रिअप्वाइंटमेंट की व्यवस्था करें, यह कुछ ठीक नही लगता है । इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इसके बारे में भी हमारी प्रवर समिति को पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके इसके बारे में सारी व्यवस्था करनी चाहिए ।

इसमें धारा ७ ई(४) में चाहा गया है . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: How much more time would you need?

SHRI V. M. CHORDIA: Ten or fifteen minutes.

उप सभापति : और दस-पन्द्रह मिनट चाहिएं ?

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया करीब १० मिनट और दे दें ।

खंड ७ ई (४) यह है :-

"If the Vice-Chancellor is of the opinion that, for the maintenance of discipline in the University, any student of the University should be expelled therefrom, he may, by order in writing, direct the expulsion of the student therefrom:".

इसमें वाइस-चांसलर को यह अधिकार दिया जा रहा है कि अगर कोई विद्यार्थी अनुशासनहीनता करे तो उसे यूनीवर्सिटी से निकाल दे । उसे यूनीवर्सिटी से निकालने का उसे अधिकार है । किसी विद्यार्थी को अनुशासनहीनता के लिए सजा देनी चाहिए और उसके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए--इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते । मगर एक वाइस-चांसलर को ही सुप्रीम अथारिटी मान कर के इसके बारे में पूर्ण अधिकार दे देना कुछ न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता । यह विद्यार्थी के जीवन-मरण का प्रश्न होता है । सम्भवतः जोश में आकर के विद्यार्थी होश खो दे और कुछ अव्यवस्था कर बैठे और उसका उसे यह परिणाम भुगतना पड़े कि जीवन भर के लिए उस विश्वविद्यालय से अलग होना पड़े, यह कुछ ठीक नहीं लगता है । मैं नम्र निवेदन करूंगा कि उसको निकालने का अधिकार हम देना चाहते हैं तो कोर्ट को यह अधिकार दें कि कोर्ट उसको निकाल सके और कोर्ट के सामने वाइस-चांसलर को जो सजेशंस रखना हों वह रखें, जो भी बात उनको करनी हो वह करें--इस आधार पर व्यवस्था हो सके तो ज्यादा अच्छा होगा ।

[श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी विद्यार्थी के जीवन के साथ कुछ ऐसा कर बैठें कि उसे जिन्दगी भर रोना पड़े । सम्भवतः वाइस-चांसलर भी कुछ जोश में कर जायें और बाद में पछतायें, लेकिन चूंकि एक बार लिख चुके हैं और वह प्वाइंट आफ प्रेस्टिज हो चुका है, इसलिए विदड्रा न करें—तो इसके बारे में हम विचार करे । अगर कोर्ट को ठीक नहीं समझें तो किसी दूसरी अथारिटी को यह अधिकार दें, लेकिन एक सामूहिक अथारिटी को इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार देना चाहिए । एक व्यक्ति विशेष की इच्छा पर या एक व्यक्ति विशेष की नाराजी पर विद्यार्थी का सारा जीवन समाप्त हो जाये, यह ठीक नहीं है । इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में प्रवर समिति पुनर्विचार करे ।

खंड ७ ई (७) में बताया गया है कि वाइस-चांसलर एमर्जेंसी के समय जो भी उचित समझे वह कार्यवाही कर सके । इसमें यह दिया है :—

"If, in the opinion of the Vice-Chancellor, any emergency has arisen which requires immediate action to be taken, the Vice-Chancellor shall take such action as he deems necessary and shall report the same for approval at the next meeting to the authority which, in the ordinary course, would have dealt with the matter:"

और आगे बताया है :—

"Provided that, if the action taken by the Vice-Chancellor is not approved by the authority concerned, he may refer the matter to the Visitor, whose decision thereon shall be final:".

अब ऐसी स्थिति में अगर कहीं एमर्जेंसी के अन्तर्गत जो अधिकार दूसरे को है, वह वाइस-चांसलर काम में लाए और उसे काम में लाने के परिणामस्वरूप तुरन्त ही जिस अथारिटी का वह अधिकार है उसकी स्वीकृति प्राप्त करना चाहे, मगर कहीं अगर वह अथारिटी स्वीकृति नहीं देती है, अपनी सहमति नहीं देती है तो उसके लिए इसमें व्यवस्था की है कि विजिटर के निर्णय के लिए भेजा जाये । लेकिन इन-केस विजिटर भी सहमति नहीं देते हैं और कोई ऐसा कार्य किया जा चुका है जो कि "अनडन" नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में क्या परिस्थिति होगी, क्या किया जायेगा, इसके बारे में भी मन्त्री महोदय और प्रवर समिति विचार करें, तो अधिक अच्छा होगा; क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि कोई काम हमारे वाइस चांसलर कर बैठें और जिसको ठीक नहीं किया जा सकता हो—विजिटर भी उसके लिए एग्री न करे और वह अथारिटी भी एग्री नहीं करे—तो ऐसी स्थिति में उस काम का क्या होगा ? इसके बारे में भी विचार करना अत्यन्त आवश्यक है ।

खण्ड १० के अन्तर्गत नया उपखण्ड ९ (५) जो बना है उसमें यह है कि कोई बात दिन-दिन के कार्यों से सम्बन्धित है या नहीं, इसका निर्णय विजिटर करेंगे, लेकिन अगर विजिटर की अपेक्षा कोर्ट को यह अधिकार दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । वैसे हम और आप चाहते हैं कि कोर्ट के अधिकार बढ़ायें और उसकी सुप्रीमेसी को बनाए रखें, लेकिन यह जो अप्रत्यक्ष रूप से विजिटर का अधिकार बढ़ाते जा रहे हैं, यह मुझे कुछ ठीक लगता नहीं है ।

इसमें खण्ड १२ में अयोग्यता निवारण के बारे में चर्चा है और अयोग्यता के बारे में यह है कि अमुक-अमुक प्रकार के आदमी नियुक्त नहीं किए जा सकते और खण्ड १२ए (१) (सी) में यह बताया है :—

"He has been convicted by a court of an offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less

than six months, and a period of five years has not elapsed since his release."

शिक्षा का ऐसा क्षेत्र है कि अगर मारल टरपीट्यूड के लिए एक रोज की भी सजा हुई हो तो हमें उसे रखना नहीं चाहिए; क्योंकि यहां छात्र और छात्राओं का सम्बन्ध है और नैतिकता से इस क्षेत्र का बहुत बड़ा सम्बन्ध है । अगर किसी आदमी को मारल टरपीट्यूड में इनवाल्व्ड होने की वजह से सजा हुई हो—चाहे उसको ६ महीने से कम की भी सजा मिली हो और चाहे उसको पांच साल भी बीत गए हों—ऐसे खराब आदमी को विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रखने की आवश्यकता है ही नहीं । या तो हमारी यह कल्पना हो कि हमको अच्छे आदमी मिलेंगे ही नहीं और ऐसे आदमी ही मिलेंगे जो कि मारल टरपीट्यूड में इनवाल्व्ड हुए हों, उनके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है, नहीं तो मैं ठीक नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों रखा है? मेरा नम्र निवेदन है कि जो मारल टरपीट्यूड में इनवाल्व्ड हों उनको चाहे कोर्ट के उठने तक की सजा ही दी गई हो, नहीं रखना चाहिए । मेरा निवेदन यह है कि छात्र और छात्राओं का मामला जरा डेलिकेट होता है और अगर इस डेलिकेट मामले में मारल टरपीट्यूड में इनवाल्व्ड आदमी फंस जायें तो बड़ा बुरा हो जायेगा । इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस बारे में पुनर्विचार करें और मारल टरपीट्यूड के लिए एक घंटे की सजा भी दी गई हो तो भी ऐसे आदमी को विश्वविद्यालय के अधिकारियों में नहीं आने दें और इस दृष्टि से इसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है । इसी के सम्बन्ध में जो दूसरा खण्ड १२ बी उपखण्ड (ई) है, उस पर भी विचार किया जाना आवश्यक है ।

अब, खंड १३ द्वारा धारा १४ में संशोधन चाहा गया है । धारा १४ में पहले यह व्यवस्था थी कि इस यूनीवर्सिटी को रिकरिंग खर्चा चलाने के लिए ५० लाख रुपया इनवेस्ट करने का अधिकार था और यह व्यवस्था थी कि उस इनवेस्टमेंट से जो आमदनी आए उससे इसका रिकरिंग खर्चा चलाया जाये । अब इस व्यवस्था में यह संशोधन करना चाहते हैं कि ५० लाख के बजाय ४५ लाख रह जाये । मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो खर्चा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हम पूंजी से जो आमदनी होगी उस को कम करना चाहते हैं, इस का मूल कारण क्या है? अगर हम स्थायी आमदनी के जरिये को बढ़ाते हों तब तो मुझे कुछ कहना नहीं है, नहीं तो हमें तो यह चाहिए था कि इससे अधिक रकम डिपाजिट करके उससे अधिक आमदनी बढ़ा कर दिन-दिन का रिकरिंग खर्चा चलाया जाये । तो आजकल के जमाने में जबकि रुपये की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गयी है, जहां पचास लाख पहले था उस को आज और अधिक किया जाना चाहिए था; क्योंकि पहले जितनी ५० लाख में खरीदने की ताकत थी आज के समय में उस को ७०–७५ लाख रु० में भी नहीं खरीद सकते । तो ऐसी स्थिति में उन को ५० लाख की अपेक्षा एक करोड़ का अधिकार देने की बजाय आप ४५ लाख कर रहे हैं, यह कुछ न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता, जब तक मैं इसका दूसरा पक्ष न सुन लूं । ऐसी स्थिति में मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रवर समिति इस पर पुनः विचार करे कि इसमें यह व्यवस्था क्यों की जा रही है और यह जो कमी हो रही है उसके लिए स्थायी साधन की व्यवस्था क्या की जायेगी, अन्यथा हम को इसकी वर्तमान सीमा को बढ़ाना चाहिये ।

खंड १४ द्वारा चाहा गया है कि यह यूनीवर्सिटी किसी कालेज को एफिलियेट नहीं करेगी । मेरा यह नम्र निवेदन है कि हम यह बंधन लगा दें कि अमुक क्षेत्र के अन्दर यूनीवर्सिटी का कालेज बनने वाले कालेज के अलावा किसी को यह एफिलियेट नहीं करेगा; क्योंकि आज के समय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और कालेजेज की ऐसी अवस्था है कि उनमें अकोमोडेशन मिल नहीं सकता । तो ऐसी स्थिति में अगर नए नए कालेज बनेंगे—बनारस में नए कालेज बनें—

[श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

और आप कहें उनका एफिलियेशन इस यूनीवर्सिटी से नहीं हो सकता, उनको किसी दूसरी यूनीवर्सिटी के पास जाना पड़ेगा, यह कुछ न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: How long will you carry on? You have already taken 25 minutes.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : दस-पांच मिनट और लेना है ।

उपसभापति : दस-पांच नहीं, पांच दस कहिए ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि कम से कम हम क्षेत्र निर्धारित कर दें कि इस क्षेत्र के अन्दर जो कालेजेज बनने वाले हैं या अभी हैं, अगर वे उससे एफिलियेट होना चाहते हैं तो उन को एफिलियेशन के लिये स्वीकृति जरूर दें ।

यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अलीगढ़ के क्षेत्र में ही दो कालेजेज हैं, एक तो बारहसेनी कालेज और एक धर्म समाज कालेज । दोनों चाहते हैं कि हम को अलीगढ़ यूनीवर्सिटी से एफिलियेट किया जाये, मगर वह हो नहीं पाया, परिणामस्वरूप उन को आगरा यूनीवर्सिटी के पास जाना पड़ा । यह समझ में आने सरीखी बात नहीं । एक तरफ हम सारे बन्धन तोड़ना चाहते हैं, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाना चाहते हैं, उनमें एकता का भाव पैदा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वहीं के वहीं अलीगढ़ में कालेज से अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के साथ एफिलियेट न हो सके, यह कुछ समझ में आने सरीखी बात नहीं । अगर ऐसा है कि कहीं अलीगढ़ यूनीवर्सिटी में भी यह एफीलियेशन चालू न हो जाये यदि हम यहां बंधन नहीं लगा दें, यदि यह अन्डरलाइंग आइडिया है, तो बहुत बुरा है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा . . .

DR. NIHAR RANJAN RAY (West Bengal): Is not Aligarh University a unitary one? How can it be done?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is a correction that Dr. Ray has made. Will you please repeat it for his information?

DR. NIHAR RANJAN RAY: I think Aligarh University is a unitary, residential university. So it cannot affiliate a college.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): So is Banaras University.

DR. NIHAR RANJAN RAY: So is Banaras University.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : यह तो ऐसी दलील दे दी गई है मानो यह पत्थर की लकीर हो गई है, लक्ष्मणरेखा रह गई है और इसको हम बदल नहीं सकते हैं । मेरा निवेदन है कि यूनिटरी होने से यह मतलब नहीं कि वहां के क्षेत्र के कालेज को एफिलियेट करने के वास्ते उसमें संशोधन नहीं कर सकते, उसकी व्यवस्था नहीं बदल सकते । उसको परिवर्तित किया जा सकता है, यह अपने हाथ की बात है और हम ने बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी में भी की है ।

SHRI NAFISUL HASAN: It can have its own colleges. There is no question of affiliation.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : खैर, आपका मत हो सकता है । इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि हमें एक क्षेत्र निर्धारित कर देना चाहिये कि बनारस के चालीस, पचास मील एरिया में जो भी कालेजेज का निर्माण होगा, अगर वे चाहेंगे तो उनको बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी से एफिलियेट किया जा सकेगा । ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिये और वैसा ही हमको अलीगढ़ के लिए भी करना चाहिये । इसके बारे में हमें पूरी तौर से विचार करना होगा ।

अब इसमें कोर्ट की स्वायतता के बारे में जैसा कि पूर्व में मैं निवेदन कर चुका हूं कि विजिटर्स को जो अधिकार दिये जा रहे हैं, उसमें कुछ सीमा डाली जानी चाहिये। कोर्ट को कुछ अधिकार देने चाहियें। उसमें अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व हो, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए और साथ ही यूनीवर्सिटी का प्रतिनिधित्व भी पर्याप्त मात्रा में हो, इस का विचार किया जाना चाहिये। आशा है, जिन सुझावों को मैंने दिया है उन पर प्रवर समिति और माननीय मंत्री जी विचार करेंगे।

SHRI SANKAR PRATAP SINGH DEV (Orissa): Madam Deputy Chairman, I am happy to be able to have time given to me for discussing this Banaras Hindu University (Amendment) Bill. This University, as we all know, was founded by one of India's greatest patriots, Pandit Madan Mohan Malaviyaji of happy memory. He had lofty ideals and he conceived a residential university where it will be run after the ancient *gurukuls* and *rishikuls*, where discipline would be inculcated in the better part of the day during the training of the students in an academic and saintly atmosphere, as distinct from the present day universities where indiscipline runs high. During his time as Vice-Chancellor, due to his stature and personality, he coped with the small troubles that cropped up. After him came in our beloved President, Dr. Radhakrishnan, during whose stewardship the University progressed both in its administration and in its life. But he had to give way due to group politics which started asserting. He was followed by Dr. Amarnath Jha who had also been Vice-Chancellor of Allahabad University. He kept on for some time, but he was also a victim of this groupism.

AN HON. MEMBER: Of what?

SHRI SANKAR PRATAP SINGH DEV: Of groupism.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Of groupism, he says.

SHRI SANKAR PRATAP SINGH DEV: Next came Shri Govind Malaviya, and at this time, in 1951, the Act came in and a panel was put up and Acharya Narendra Dev was selected. He did very well during his time, but due to his ill-health, he left and Shri C. P. Ramaswamy Ayyar came up. But he did not succeed in being long there though he did very much for the University, both with the Government and with the University, Grants Commission where he was a member. So, history shows that this University has always been attacked by student strikes, groupism and politics. The real menace lies in the teacher-politicians and the formation of groups which dominated in all the affairs of the University. Since teachers are becoming politicians, may I suggest that those teachers who take part in politics may be transferred before they do the mischief, and thus politics may be nipped in the bud?

Student indiscipline has attracted the active attention of every thoughtful person in India.

As is seen, it is only a group of students and their sympathising teachers who have determined the appointment of Vice-Chancellors—and their retirement—of the Banaras Hindu University, which has been pointed out by the Mudaliar Committee. Therefore, student indiscipline which takes root from pre-independence days, although it was a necessity then, has ramified itself to the point of great danger during the past so many years. There are some glaring cases where even the administration has encouraged student indiscipline as in the case of my own State, Orissa. The other day, immediately after the students got into the Orissa Assembly Chamber and had held a mock session, the Chief Minister of Orissa made a public statement that he was a student leader himself. After such an indecent incident, if the Chief Minister of a State were to declare himself as the leader of the students, it can be easily imagined as to

[Shri Sankar Pratap Singh Dev.]

what amount of encouragement this would provide to the students. Again, I give another instance. We do not know when the war was started against the students in Orissa but on the 5th of November, a great midnight treaty was signed at Bhubaneswar between the Chief Minister of Orissa and the students, but the corrupt conduct of the Orissa Ministers . . .

THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI M. C. CHAGLA): Madam, I rise on a point of order. I am sure what the hon. Member is saying is extremely interesting, but really we are dealing with the Banaras Hindu University, not with the Orissa affairs.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It has to be relevant to the subject before us.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): Madam, since the Leader of the House has raised a point of order, I am also entitled to participate in that. It is not a question of student unrest alone. We are going to deal with it on a national basis and the student unrest in Orissa, as the Prime Minister gave out in a press statement in Delhi, was so great . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all right but it is not strictly relevant, and I think Mr. Chagla has made the point.

SHRI M. C. CHAGLA: These remarks may have been relevant in respect of the other discussion on the University Grants Commission but . . .

SHRI M. RUTHNASWAMY (Madras): He is dealing with student indiscipline and this may affect the Banaras Hindu University also. That is the point he is making.

SHRI SANKAR PRATAP SINGH DEV: I only wanted to say that the Treaty of Bhubaneswar did not succeed because the students did not believe the Ministers and it was only when the Central Home Minister, Shri Gulzarilal Nanda, went there and assured the students that the assurances held out on the 5th night would be implemented that the strike was called off. I do not want the students to get entangled in the administration. As a matter of fact, what I was going to suggest was this: The Principal of the Ravenshaw College had got a Guardians' Committee formed and this Guardians' Committee did very well during the strike by the students. I would like the Joint Committee to find a place for such Guardians' Committees in this Bill so that the voice of the students will be represented in the management of the Banaras Hindu University. That is why I referred to this point. Of course, the Orissa trouble is there and I have nothing to say because that is being enquired into.

Parliament was told that a Committee had been appointed under the chairmanship of Dr. Kothari to prepare a Model University Bill. The Minister for Education should tell us what the recommendations of that Committee were and whether the Bill before us now is based on the model presented by Dr. Kothari.

India takes great pride in calling herself a secular State. Therefore, it is in the fitness of things that the name which smacks of communalism and distinctly carries the communal character should immediately be changed, particularly in the educational field which is a great medium for achieving national integration. Therefore, I would suggest that the Education Minister should bring in an official amendment to drop the word "Hindu" from the name of the Bill. The Bill is before the House for discussion and this could be done today. Once this gesture is shown, it can be taken—I mean the second step to delete the word "Muslim" from the name of the Aligarh Muslim University in a subsequent amendment.

Lastly, I would like to go through the conclusion of the Mudaliar Committee. I would just like to read a paragraph which I want to be taken into consideration carefully by the Joint Committee:

"We have suggested that a Screening Committee should review the appointments made to the teaching staff and the work of the members of the teaching staff and, where necessary, suggest steps to be taken in the light of their findings. The indiscipline so frequently exhibited in this University is due to several factors which we have stated but it appears to us that the basic factor is the attitude of the teachers, some of whom play the role of teacher-politicians and are not disinclined to exploit the grievances of the students. We have also stated that in regard to any of the University Unions and their activities, a sound convention should be established and there should be a limitation on the number of years within which students should aspire for these honorary places, as indeed there is in the field of sports. We fully realise that students have some handicaps and they should as soon as possible be remedied. We have given in detail some of the necessary amenities that the students should be given. We are of the opinion that the University should be a completely residential University and that, excepting for one college, the Kamachcha College, it should have no affiliations with other colleges; nor should it be in a position to hold examinations for private candidates and confer degrees and diplomas in such liberal measure as is being done at present. The whole object of a residential University is thus frustrated. We have made specific recommendations in regard to selection committees, appointment of examiners, constitution of boards, etc., etc."

With these words, I resume my seat.

شری عبدالغنی (پنجاب) : میڈم ڈپٹی چیرمین - یہ بل جو کہ سلیکٹ کمیٹی کی سپرد کیا جا رہا ہے مجھے اس پر کچھ زیادہ کہنے کی چاہتا نہیں تھی لیکن اس بل میں سے جو بو آتی ہے وہ کانگریس سرکار کی اس ذہنیت کی تائید کرتی ہے جو کہ ڈکٹیٹر شپ کی طرح جمہوریت کے پردہ میں بڑھتی جا رہی ہے - اس لئے مجھے خطرہ ہے کہ اگر اس ٹینڈینسی کو اس اسپرٹ کو جس اسپرٹ کو کانگریس سرکار آئے دن نئے نئے بل لاتی ہے ڈسکریج نہ کیا جائے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ ملک بالکل ڈیموکریسی کے حقوق کو کھو بیٹھے گا یہ جو ہم نے بڑی محنت اور قربانی کے بعد حاصل کی ہے - اس بل کے تحت اتنے اڈھیکار دبئے جا رہے ہیں جو شاید ہی کسی ڈکٹیٹرانہ ملک میں نہ ہوں اور یہ اڈھیکار وائیس چانسلر کے لئے مانگے جا رہے ہیں -

آخر ایک یونیورسٹی میں جھگڑے ہوئے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اپنی حد سے تجاوز کر گئے - یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ایسے ڈیفیکٹس آگئے تھے جس سے انہوں نے پالیٹیکس میں حصہ لیا ہو اور اس سے یونیورسٹی کی جو شان ہے اس کو دھکا لگا اور ایڈمنسٹریشن سے

[شری عبدالغنی]

ان کا ٹکراو ہوا لیکن اس کا یہ نتیجہ تھوڑا ہی ہونا چاہیئے کہ اس بل کو لایا جائے جس بل کے معنی یہ ہوں - اور مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑے آنریبل ممبر ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایجوکیشن میں بتائی جو ایک بڑی پروگریسو پارٹی کے چیر مین ہیں یعنی انہیں کے ساتھ ٹیچروں میں اتنا خوف پیدا کر دیا جائے کہ وہ ان سے بھی کچھ نہ کہہ سکیں - آپ یہ لانا چاہتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کو ایسا بنا دیا جائے کہ جس میں کسی کو یہ جرات نہ ہو کہ وہ آزادی سے رائے کا اظہار کر سکے -

میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اسٹوڈنٹوں میں ایک ذمہ داری آنی چاہیئے - میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اسٹوڈنٹوں میں ڈسپلن آنا چاہیئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مانتا ہوں کہ اسٹوڈنٹوں کو ایکٹو پالیسی سے جتنا دور رکھا جائے اتنا ہی ٹھیک ہے میں یہ مانتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز میں تجاوز کرتے ہیں - اگر ریزن ایبل اپورچونیٹی دینے کے بعد بھی ضروری سمجھا جائے کہ وہ اپنی عادت کو نہیں بدلتا تو اس کو کچھ عرصہ کے لئے اپنے تعلیم کے حقوق سے محروم بھی کر دیا جائے تو ایسی کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے لیکن اس کے معنی اگر یہ لئے جائیں جیسا کہ اس بل میں آیا ہے تو مجھے ڈر ہے . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ghani, how much more time will you take?

شری عبدالغنی : ابھی تو میڈم - میں نے شروع ہی کیا ہے - میں تو کم سے کم اس پر آدھے گھنٹہ بولوں ہی -

उपसभापति : आधा घंटा बोलेंगे;

شری عبدالغنی : اگر آپکی مرضی ہوئی - اجازت ہوئی تو بولوں گا - آپ اجازت نہیں دیں گی تو میں بیٹھ جاؤں گا -

उपसभापति : आप बोल सकते हैं। मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हूं कि आप कितना टाईम लेंगे क्योंकि एक बज चुका है।

شری عبدالغنی : میں تو ابھی اور اسی پر بولوں گا - (Interruptons)

میں تو بل ہی پر بول رہا ہوں . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am asking you because it is one o'clock now. If you can finish soon, we will wait.

Otherwise the House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half past two of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

شری عبدالغنی: میڈم ڈپٹی چیرمین - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ

غلط راستے اختیار کئے - اس پر سرکار نے کمیٹیاں بٹھائیں - پہلی کمیٹی نے کچھ سفارشات کیں اور اس کے بعد بھی بڑی لے دے ہوئی - چوں کہ سرکار کچھ ایسے راستے اختیار کرتی چلی جا رہی ہے یا سرکار کے چاہنے والے جو ہیں مختلف انسٹی ٹیوشنس میں وہ کچھ ایسے راستے اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کل جب ہمارے لیڈر مسٹر اے - ٹی منی نے یہ کہدیا کہ جو چیپ پالیٹیشنس ہیں ان کو بھی ڈاکٹر کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں تو اس کے جواب میں یہ کہدیا گیا کہ بھائی جرنلسٹوں کو مانئے ہو تو مسٹر اے - ٹی منی کو بھی مانے - میڈم ڈپٹی چیر مین - مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ مسٹر اے - ٹی منی کی قابلیت کے بہت کم اس وقت ہندوستان میں پالیٹیشنس ہیں - اگر کسی کو ناگوار گزرے تو میرا خیال ہے کہ اس کو حق پہنچتا ہے ایسی رائے قائم کرنے کا کہ وہ اے - ٹی منی کی قابلیت کا جو اس وقت ملک کی بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اس کا مذاق اڑائیں - لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس وقت یونیورسٹیوں نے اپنی شان کو اپنی ان ڈگریوں کو - کہ جن کی بڑی شان تھی دنیا میں اور ہندوستان کی ٹیکسلا اور پاٹلی پتر کی یونیورسٹیاں جو ڈگریاں دیتی تھیں دنیا بھر میں

اس بل کے لانے سے سرکار کچھ ریجیکٹ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ تمام ملک کی شکتیوں کو اپنی مٹھی میں کر لے اور اس کا صدمہ مجھے یوں ہے کہ مسٹر چھاگلا جن کی قابلیت کی چھاپ میرے دل پر لگی ہوئی ہے اور جن کے لئے میرے دل میں بڑی عزت ہے وہی اس بل کے لانے کا باعث ہوئے ہیں -

اس بل میں کئی طرح کے پوائنٹ اٹھائے گئے اور وہ جو پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں ان میں وائس چانسلرز کے لئے بہت زیادہ اختیارات دینے کے لئے کوشش کی گئی ہے - میں سمجھتا تھا کہ مسٹر چھاگلا تمام ملک کی یونیورسٹیوں کے لئے ایک ایسا کمپریہنسو بل لائیں گے جس میں اسٹوڈنٹس کے حقوق اسٹوڈنٹس کی ذمہ داریاں ٹیچرس کے حقوق ٹیچرس کی ذمہ داریاں اور وائس چانسلر یا اس کے نیچے جو اسٹاف ہے اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داریاں ان سب کو اس طرح سے دیا جائے گا کہ جس میں ہمارے ملک کی جو یہ خواہش ہے کہ ہم ڈیمو کریسی کے بہت بڑے علم بردار ہوں وہ بھی قائم رہے اور ہمارے ملک کو کسی طرح کا نقصان بھی نہ ہو -

پچھلے دنوں بنارس یونیورسٹی میں کچھ غلطیاں ہوئیں اور اس طرح اس کے بعد کئی جگہ اسٹوڈنٹس نے کچھ

[شری عبدالغنی]

کے لئے یہ بھی مشکل ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو جگہ دے سکیں اپنی کلاسز میں - تو ایسی حالت میں جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک سارا کا سارا پڑھا لکھا ہو جائے تو ہمیں ایک بل ایسا یونیورسل بنانا چاہیئے جس میں ساری یونیورسٹیوں کے لئے ایک سا راستہ دکھایا جائے - سارے وائس چانسلرس کے لئے ایک سے راستے اور حقوق مقرر کئے جائیں - اور یہ کیا ضروری ہے کہ ایک ہی وائس چانسلر کو دوسری بار بھی مقرر کیا جائے - کوئی بڑا قابل ہو چاہے ڈاکٹر رادھا کرشنن تھے یا مسٹر چھاگلا ہیں تو کیا کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی ان سے ریکویسٹ نہ کی جائے - ان کو پھر سے انتخاب کرنے کی شاید ضرورت ہی محسوس نہ ہو - انسٹی ٹیوشنس جو ہیں یونیورسٹیاں جو ہیں یا ان کے ادھیکاری جو ہیں وہ خود یہ خود ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہماری راہنمائی کریں آپ ہماری سیوا کریں لیکن یہاں تو اس طرح سے کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ ادھیکار اپنے آدمیوں کو دیئے جائیں -

اگر کوئی شکوہ نہ کرے تو میں کہوں گا کہ ابھی ابھی پھول پور میں ہمیں شکست ہوئی اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں بھارت کا بڑا اس سے مان تھا لیکن آج انہوں نے اپنی ڈگریوں کو بڑا چیپ کر دیا ہے -

اس میں کوئی راستہ ایسا نکالنا چاہیئے مسٹر چھاگلا کو کیوں کہ خدا نے ان کو بڑی قابلیت دی ہے کہ وہ ایسا بل لائیں جس سے یونیورسٹیاں یہ کہنے پر مجبور نہ ہوں کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے - آپ میڈم ڈپٹی چیئرمین - جانتی ہیں کہ جب دیش غیروں کے ہاتھ میں تھا تو ان کو حق پہنچتا تھا کہ ہمارے بچوں کی ترقی میں ہمارے اسٹوڈنٹس کی ترقی میں اور ہمارے ٹیچروں اور پروفیسروں کی ترقی میں وہ رکاوٹیں ڈالیں اور جتنی رکاوٹیں وہ ڈالتے تھے اتنا ہی وہ سمجھتے تھے کہ ان کے لئے اچھا ہے - وہ ہمارے ملک کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے تھے - اب جب اپنی سرکار بنی ہے تو اس کو اس بات کا بھی احساس ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں ۱۰۰ فی صدی پڑھے لکھے ہو جائیں تاکہ وہ اپنی نیکی اور بدی کو سمجھ سکیں تو یہ مسٹر چھاگلا تسلیم کریں گے کہ اس وقت نہ صرف ٹیکنیکل کالجز میں جگہ نہیں ہے اور یونیورسٹیاں ٹیکنیکل کالجز کو اپنا نہیں سکتیں چاہے وہ انجینئرنگ کالج ہو چاہے وہ میڈیکل کالج ہو چاہے وہ ایگریکلچرل کالج ہو ان

شکست ہوئی لیکن اس کو بھی
تسلیم کرتا ہوں کہ وہاں اسٹوڈنٹس
کے غول کے غول باقاعدہ جتھوں کی
شکل میں سرکار کے اشارہ پر کام کر
رہے تھے اور ٹیچرس کام کر رہے تھے
وہاں کمبل بٹ رہے تو وہاں طرح
طرح کے کپڑے بٹ رہے تھے اور پرمٹ
بٹ رہے تھے -

श्री महाबीर प्रसाद भार्गव (उत्तर प्रदेश) : क्या गनी साहब का यह कहना है कि आपके लिये काम नहीं कर रहे थे स्टूडेंट्स और टीचर्स?

شری عبدالغنی : پہلے میں نے کہا
تھا جب مہودے نے مجھے اجازت دی
تھی کہ اسٹوڈنٹس کو جتنا پالیٹکس
سے باز رکھا جائے اتنا ہی دیش کے
ہت میں ہوگا - میں نے یہ نہیں
کہا تھا کہ وہ اپوزیشن کے لئے کام
کریں اور سرکاری پارٹی کے لئے کام
نہ کریں - جہاں مسٹر چھاگلا یہ
چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن
تربیت کے سلسلہ میں کھلے
ایجوکیشن کے سلسلہ میں کھلے جو
سرکار سے بندھا ہوا نہیں ہے - جو
اپنے من مانی طور پر چلتا ہے اس
کو ممنوع قرار دیا جائے - میں چاہتا
ہوں کہ کچھ یونیورسٹیاں ایسی بھی
کھولی جائیں جن کے لئے اس طرح
کے نیم مقرر کئے جائیں کہ اگر ۲۵
ہزار کی اجازت دی تو ۲۵ ہزار ہی
خرچ ہوں - ۲۵ لاکھ خرچ نہ ہوں

آپ ہمیں شکست دیجئے ہمیں
شکست سے کوئی تکلیف نہیں ہے
لیکن لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پھر
آ کر یہ کہنا کہ ہم نے ۲۵ دیئے
وہ کوئی معقول بات نہیں ہے -

بہر حال میں یہ کہہ رہا تھا
کہ ایک یونیورسل بل آنا چاہیئے -
سلیکٹ کمیٹی جو اس بل پر بیٹھ
رہی ہے اس کے معزز ممبران اور
مسٹر چھاگلا سے میں یہ عرض کروں
گا کہ کوئی یونیورسل بل لائیے اور
اس بات کو نہ بھولئیے کہ ہمارا
دیش ایک ایسا دیش ہے جس نے
آتما اور پرماتما کے گیان کو دنیا
میں پھیلایا اور روحانیت کی طرف
جس کا بڑا رخ ہے - آج ہماری تعلیم
جس ڈھنگ سے دی جاتی ہے اس
کے سلسلہ میں میں یہ کہوں گا
کہ میں میٹر کا مخالف نہیں ہوں
میں یہ نہیں کہتا کہ مادہ کچھ
بھی نہیں ہے لیکن مادہ پرستی
بری ہے - تو اگر اسی طرف ہم
اپنی ایجوکیشن کو لے جائیں گے
تو مجھے خطرہ ہے کہ ہمارے ملک
کی جو شان ہے اور جو ہزار ہا برس
سے ہمارا دیش سب کا اگوا رہا ہے
وہ بہت پچھڑ جائے گا - میں
رکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی سلیکٹ
کمیٹی کے معزز ممبران ہوں وہ
میری اس گذارش کے بارے میں

[شری عبدالغنی]

بڑی وچار کریں اور وچار کر کے پھر ایک ایسا راستہ ڈھونڈھیں جس سے ہمارا ملک بچھڑ نہ جائے - آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج لوک سبھا بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اگر سرکار اسی طرح سے سب اختیارات کو سکوڑتی چلی گئی تو وہ دیش کے لئے نقصان دہ ہوگا- انہوں نے اگر انڈسٹری کا کوئی اختیار لیا تو شاید اسی حد تک ان کو دنیا معاف کر دے کہ بھائی نیشنلائز کرنا تھا اور کام نہیں چلتا تھا پبلک سیکٹر کے بغیر اس لئے کچھ نہ کچھ کہا گیا - چونکہ بعض اتنے بڑے کام ہیں کہ ان کو ٹاٹا برلا اور ڈالمیا اور سنگھانیا سب مل کر بھی نہیں کر پاتے - جب تک کہ سرکار ان کو اپنے ہاتھ میں نہ لے - ٹیکنیکل انسٹی ٹیوشن اگرچہ کچھ لوگوں نے یا اچھے آدمیوں نے قائم کئے ہیں لیکن اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بھی اگر سارے الگ الگ چلتے رہے تو نیشنل انٹیگریشن کا جو مقصد ہے وہ شاید غصب ہو جائے گا - مجھے ایک بات کا یو-پی میں احساس ہوا اور میرا یقین ہے کہ اس پر نہ صرف مسٹر چھاگلا بلکہ ہر اچھے دل کے بھائی چاہے وہ ہندو بھائی ہوں سکھ بھائی ہوں مسلمان بھائی ہوں ہریجن بھائی ہوں عیسائی بھائی ہوں سب نے سب وچار کریں گے - بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے آزادی ملنے کے پہلے مسلمانوں کی جتنی دینی تعلیم تھی وہ اردو رسم الخط میں تھی اور مسلمانوں کی جتنی پرانی تاریخ ہے جتنی ان کی روایات ہیں چاہے وہ حدیث ہو شریعت ہو سب کی سب اردو رسم الخط میں ہے لیکن اب وہاں اسکولوں میں اردو رسم الخط مٹنا چاہتی ہے بلکہ میں کہوں گا کہ مٹ گئی ہے - تو ایسی حالت میں کیا چھاگلا صاحب یہ ممنوع قرار دیں گے - کیسے مسلمان بچے ایمان کو بچائیں گے - وہ بھارت کی تہذیب کو بھارت کے اتہاس کو بھارت کی سبھیتا کو جہاں سیکھیں وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین کو بھی سیکھیں اور اپنے دین سے بالکل لا دین نہ ہو جائیں - اس لئے اگر اسے ممنوع قرار دیں اور یونیورسٹیوں میں یا دوسری جگہ ایسی فضا پیدا کی جائے تو پھر کیا ہوگا - کہتے ہیں کہ دس بچے نہیں ہوں تو نہیں ہوگا لیکن میں جہاں گیا وہ سو فی صدی مسلمان گاؤں ہے پھر بھی وہاں اردو نہیں تھی - میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی بل میں سے اسے . . .

श्री आबिद अली (महाराष्ट्र) : जनाब उर्दू को मुसलमान की ही जबान क्यों मान रहे हैं, वह हुनों की है ।

چاہتے ہیں پچاس لاکھ کی بجائے ۴۵ لاکھ کرنا چاہتے ہیں - میں ۴۵ لاکھ اور ۵۰ لاکھ کے جھگڑے میں نہیں پڑتا میں تو اس اسپرٹ کے خلاف ہوں - اگر واقعی آپ یونیورسٹیوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیاں دیش کے کام آئیں دیش کی عین منشا کے مطابق چلیں اور اس میں وہی بات چلے جو کہ سرکار چاہتی ہے چاہے یہاں کوئی سرکار بیٹھی ہو چاہے وہ سوشلسٹ ہوں چاہے وہ ہمارے شاستری جی ہوں ان کی جو خواہشات ہیں اور جس طرح وہ ملک کو پلان کر کے آگے چلانا چاہتے ہیں یونیورسٹیاں ان کا باعث بنیں تو میں مانتا ہوں کہ ان کو ضرور کچھ راستہ نکالنا چاہیئے - وہ جو راستہ نکالنا چاہتے ہیں اس میں میں ان کے ساتھ ہوں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ ملک کے لوگ جو یہاں بسے ہیں ان کے لئے کیا ٹھیک ہے - مسٹر چھاگلا شاید اس کو برا نہیں مانیں گے اگر میں کہوں کہ آج یونیورسٹیوں سے پاس ہوئے کسی ایم - اے کو لے لیجئے اور اس سے پوچھئے کہ اپنے یہاں گندم اپنے یہاں بیج کتنا ہوتا ہے تو وہ بتا نہیں پائے گا - دیش کا جو مت ہے دیش کی جو سمسیا ہے اس کو وہ صاحبان بتا

شری عبدالغنی : عابد علی صاحب - آپ اس کو مسلمان کی زبان کہیں یا ہندو کی زبان کہیں اور میں جانتا ہوں کہ اس میں ترلوک چند مرحوم، جگناتھ آزاد، فراق اور نامعلوم کتنے ہیں میں ایک ایک کا نام نہیں لوں گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہندوؤں کا اتہاس ہندوؤں کی مذہبی روایات ہندوؤں کا مذہب و دین دیو ناگری میں ہے اور مسلمانوں کا مذہب مسلمانوں کی روایات مسلمانوں کا اتہاس مسلمانوں کا دین نوے فی صدی اردو رسم الخط میں ہے - یہ ایک حقیقت ہے جس کو چھپا نہیں سکتے - میرا عرض کرنا یہ تھا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بڑی افراتفری کی اجازت دیں کوئی بے چینی قائم کریں اس کے حق میں میں نہیں ہوں لیکن جہاں مجبوری ہے اس کے لئے کوئی راستہ نکالا جائے یہ بھی دیکھنا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ اس دیش والوں کو نکالنا پڑے گا کیونکہ ہندو بڑا بھائی ہے اور مسلمان چھوٹا بھائی ہے اسے چھوٹے بھائی کے لئے دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کے راستہ میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آتی ہے اور اگر آتی ہے تو سلیکٹ کمیٹی کو اس پر بھی کچھ وچار کرنا چاہیئے -

اب رہا یہ سوال جو کہ چودریا جی نے اٹھایا کہ آپ یہاں اور سکوزنا

تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ چھاگلا صاحب سے مجھے نہ صرف محبت ہے بلکہ ان سے مجھے عقیدت بھی ہے - وہ ملک کے قابل ترین نیتاؤں میں ہیں وہ چاہے کانگریس میں ہوں یا جنج رہے ہوں کہیں بھی رہے ہوں انہوں نے اپنی قابلیت کا سکہ جمایا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میری درخواستوں پر توجہ دیں گے - اور یونیورسٹیوں میں پھر سے ایسی شان پیدا کریں گے کہ اُن کی ڈگریاں چیپ نہ ہوں اور چیپ لیڈرشپ کے لئے ڈگریاں نہ دی جائیں - یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ ہمیں ان کی شان کو قائم رکھنا ہے - مجھے یقین ہے کہ وہ میری باتوں پر توجہ دیں گے -

میڈم ڈپٹی چیرمین صاحبہ - میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا موقعہ دیا - میں نے جنرل بحث کی بجائے اس کے کہ ایک ایک دھارا پر بحث کرتا وہ بحث تو صرف کمیٹی میں ہوگی اور جب سلیکٹ کمیٹی کے بعد یہ بل آئے گا تب وقت آئے گا کہ اس کی ایک ایک دھارا پر کچھ عرض کروں اس میں کچھ آپ کی مدد کر سکوں اور کچھ ترمیم پیش کر سکوں - اس وقت تو مجھے جنرل طور پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ بل جولایا گیا ہے اس کو بدلنا چاہیئے یا نہیں اس کی اسپرٹ کو

[شری عبدالغنی]

نہیں پاتے - وہ کیوں نہیں بتا پاتے اس لئے کہ ہمارے یہاں دنیا کے باقی ممالک کے مقابلہ میں اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں میں اور ان کے یہاں میں بہت فرق ہے - وہ کیوں جنرل نالج میں اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کیوں وہ اپنے ملک کی ہر مشکل کو ہر ازچن کو ہر دقت کو جانتے ہیں - اگر کوئی بھائی برا نہ مانے تو میں کہوں گا کہ سوائے رفیع صاحب کے جو کہ ہر فن مولا تھے اور کوئی نہیں ہے کہ کسی مضمون پر کھڑا کر دیا جائے اور بولنے کے لئے کہدیا جائے - انہوں نے اگر ڈاکخانہ کو سنبھالا کمیونیکیشن کو سنبھالا تو اتنا سنبھالا کہ دنیا یاد کرتی ہے - فوج پر آئے تو اتنا سنبھالا کہ دنیا یاد کرتی ہے لیکن شاید آج ہر منسٹر کے لئے یہ مشکل ہے کہ ہر فن مولا ہو - تو ہم ایسا اسٹینڈرڈ یونیورسٹیوں کا بنا سکیں جس میں کہ لڑکے جہاں ایک کلرک بننے کی صلاحیت حاصل کریں وہاں لڑکے آفیسر بننے کی صلاحیت بھی حاصل کریں - وہ ملک کے سب سے بڑے سیوک ہوں ملک کے سب سے بڑے سپاہی ہوں ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہوں ان میں اتنی صلاحیت پیدا کی جائے -

بدلنا چاهیئے یا نہیں اور کسی طرح سے اسے ایک یونیورسل بل بنانا چاهیئے تاکہ ایک ہی بل ساری یونیورسٹیوں پر لاگو ہو اور ملک میں جو اسوقت کمی آ گئی ہے وہ دور ہو - جو ہم بچوں کو جگہ نہیں دے پاتے ہم بچوں کی پوری طرح حفاظت نہیں کر پاتے ہم بچوں کی پوری مدد نہیں کر پاتے ہم ان کو پورے وظیفے نہیں دے پاتے - ہم ان کو باہر کے ملکوں میں نہیں بھیج پاتے ان سب میں آسانی پیدا ہو - خدا کرے چھاگلا صاحب یہاں رہیں کانگریس سرکار یہاں رہے وہ جگ جگ جئے اس کا ہمیں دکھ نہیں ہے کہ وہ پہلے دور میں جیتے یا کہیں جیتے وہ جیتے اور جئے لیکن یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ میری جو درخواستیں ہیں ان پر توجہ دی جائے - آپ کا شکریہ -

†[**श्री अब्दुल ग़नी** (पंजाब) : मैडम डिप्टी चेयरमैन, यह बिल जो कि सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जा रहा है मुझे इस पर कुछ ज्यादा कहने की चिन्ता नहीं थी । लेकिन इस बिल में मे जो बुराई है वह कांग्रेस सरकार की इस जहनियत की ताईद करती है जो कि डिक्टेटरशिप की तरह जम्हूरियत के पर्दे में बढ़ती जा रही है । इसलिये मुझे खतरा है कि अगर इस टेन्डेन्सी को इस स्पिरिट को, जिस स्पिरिट को कांग्रेस सरकार आये दिन नये-नये बिल लाती है, डिसकरेज न किया जाये तो मुझे डर है कि यह मुल्क बिल्कुल डेमोक्रसी के हकूक को खो बैठेगा जो इस ने बड़ी मेहनत और कुर्बानी के बाद हासिल की है । इस बिल के तहत इतने अधिकार दिये जा रहे हैं जो शायद ही किसी डिक्टेटराना मुल्क में न हों और यह अधिकार वाईस चांन्सलर के लिये मांगें जा रहे है ।

आखिर एक यूनिवर्सिटी में झगडे हुए और आप कह सकते हैं कि स्टूडेण्ट अपनी हद से तजावज कर गये । यह भी कह सकते हैं कि इन में ऐसे डिफेक्ट्स आ गये थे जिस से उन्होंने पालिटिक्स में हिस्सा लिया हो और इस से यूनिवर्सिटी की जो शान है इस को धक्का लगा और एडमिनिस्ट्रेशन से इनका टकराव हुआ लेकिन इस का यह नतीजा थोड़े ही होना चाहिए कि इस बिल को लाया जाये जिस बिल के मायने यह हों । और मुझे हैरत यह होती है कि एक बहुत बड़े आनरेबिल मैम्बर हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िन्दगी एजूकेशन में बिताई, जो एक बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी के चेयरमैन हैं यानी इन्ही के साथ टीचरों में इतना खौफ पैदा कर दिया जाये कि वह इन से भी कुछ न कह सकें । आप यह लाना चाहते हैं कि एक यूनीवर्सिटी को ऐसा बना दिया जाये कि जिस में किसी को यह जुर्रत न हो कि वह आज़ादी से राय का इजहार कर सके ।

मैं इस बात को मानता हूं कि स्टूडेण्टों में एक जिम्मेदारी आनी चाहिये । मैं यह भी मानता हूं कि स्टूडैण्टों में डिसिप्लिन आना चाहिये और साथ ही साथ यह भी मानता हूं कि स्टूडैण्टों को एक्टिव पालिसी से जितना दूर रखा जाये उतना ही ठीक है । मैं यह मानता हूं कि स्टूडेण्ट यूनिवर्सिटीज में तजावज करते है । अगर रीजनेबिल अपार्चुनिटी देने के बाद भी जरूरी समझा जाये कि वह अपनी आदत को नहीं बदलता तो उस को कुछ अर्सा के लिए अपने तालीम के हकूक से महरूम भी कर दिया जाये तो ऐसी कोई घबराहट की बात नहीं है । लेकिन इस के मायने अगर यह लिये जायें जैसा कि इस बिल में आया है तो मुझे डर है.

†[ ] English translation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ghani, how much more time will you take?

श्री अब्दुल ग़नी : अभी तो मेडम मैंने शुरू ही किया है, मैं तो कम से कम इस पर आधे घंटा बोलूंगा ही ।

उपसभापति : आधा घंटा बोलेंगे ?

श्री अब्दुल ग़नी : अगर आप की मर्जी हुई, इजाजत हुई तो बोलूंगा । आप इजाजत नही देंगी तो मैं बैठ जाऊंगा ।

उपसभापति : आप बोल सकते हैं । मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हूं कि आप कितना टाइम लेंगे । क्योंकि एक बज चुका है ।

श्री अब्दुल ग़नी : मैं तो अभी और इस पर बोलूंगा (*Interruptions*) मैं तो बिल ही पर बोल रहा हूं . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am asking you because it is one o'clock now. If you can finish soon, we will wait.

Otherwise, the House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half past two of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्री अब्दुल ग़नी : मेडम डिप्टी चेयरमेन, मै यह अर्ज कर रहा था कि इस बिल के लाने मे सरकार कुछ रिजिड होती चली जा रही है कि वह तमाम मुल्क की शक्तियों को अपनी मुट्ठी मे कर ले । और इस का सदमा मुझे यों है कि मिस्टर चागला जिन की काबिलियत की छाप मेरे दिल पर लगी हुई है और जिनके लिये मेरे दिल में बड़ी इज्जत है वही इस बिल के लाने का वाइस हुये है ।

इस बिल में कई तरह के प्वाइन्ट उठाये गये और वह जो प्वाइन्ट उठाये गये हैं इन में वाइस-चान्सलर के लिये बहुत ज्यादा इख्तियारात देने के लिए कोशिश की गई है । मैं समझता था कि मिस्टर चागला तमाम मुल्क की यूनीवर्सिटियों के लिए एक ऐसा कम्प्रेहेन्सिव बिल लायेंगे जिस में स्टूडैण्ट्स के हकूक, स्टूडैण्ट्स की जिम्मेदारियां, टीचर्स के हकूक, टीचर्स की जिम्मेदारियां और जो वाइस-चान्सलर या उस के नीचे जो स्टाफ है उस के हकूक और उस की जिम्मेदारियां इन सब को इस तरह से दिया जायेगा कि जिस में हमारे मुल्क की जो यह ख्वाहिश है कि हम डैमोक्रेसी के बहुत बड़े अलमबरदार हों वह भी कायम रहे और हमारे मुल्क को किसी तरह का नुकसान भी न हो ।

पिछले दिनों बनारस यूनीवर्सिटी में कुछ गलतियां हुई और इस तरह इस के बाद कई जगह स्टूडैण्ट्स ने कुछ ग़लत रास्ते इख्तियार किये । इस पर सरकार ने कमेटियां बिठाई । पहली कमेटी ने कुछ सिफारिशात की और इस के बाद भी बड़ी ले-दे हुई । चूंकि सरकार कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार करती चली जा रही है या सरकार के चाहने वाले जो है मुख्तलिफ इन्सटीट्यूशन्स में यह कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार करते चले जा रहे हैं कि कल जब हमारे लीडर मिस्टर ए० डी० मणि ने यह कह दिया कि जो चीप पालिटीशियन्स हैं इन को भी डाक्टर की डिग्रियां दी जा रही हैं तो इस के जवाब में यह कह दिया गया कि भाई जर्नलिस्टों को मिलनी हों तो मिस्टर ए० डी० मणि को भी मिले । मैडम डिप्टी चेयरमैन, मुझे इस में ज़रा भी शक नही कि मिस्टर ए० डी० मणि की काबिलियत के बहुत कम इस वक्त हिन्दुस्तान में पालिटीशियन्स है । अगर किसी को नागवार गुजरे तो मेरा ख्याल है कि इस को हक पहुंचता है ऐसी राय कायम करने का कि वह श्री ए० डी० मणि की काबिलियत का, जो इस वक्त मुल्क की

बहुत बड़ी ख़िदमत सरअंजाम दे रहे हैं, इस का मज़ाक उड़ायें। लेकिन इस में भी कोई शक नहीं कि इस वक्त यूनीवर्सिटियों ने अपनी शान को, अपनी न डिग्रियों को, कि जिन की बड़ी शान थी दुनिया में और हिन्दुस्तान की टेक्सला और पाटली पुत्र की यूनिवर्सिटियां जो डिग्रियां देती थी दुनिया भर में भारत का बड़ा इससे मान था, लेकिन आज उन्होंने अपनी डिग्रियों को बड़ा चीप कर दिया है।

इस में कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिये मिस्टर चागला को क्योंकि खुद ने इन को बड़ी काबिलियत दी है कि वह ऐसा बिल लाएं जिस से यूनीवर्सिटियां यह कहने पर मजबूर न हों कि इन के पास जगह नहीं है। आप, मैडम डिप्टी चेयरमैन, जानती है कि जब देश ग़ैरों के हाथ में था तो उन को हक पहुंचता था कि हमारे बच्चों की तरक्की में, हमारे स्टूडेन्ट्स की तरक्की में और हमारे टीचर्स और प्रोफैसर्स की तरक्की में वह रुकावटें डालें और जितनी रुकावटें वह डालते थे उतना ही वह समझते थे कि इन के लिये अच्छा है। वह हमारे मुल्क को अंधेरे में रखना चाहते थे। अब जब अपनी सरकार बनी है तो इस को इस बात का भी एहसास है और वह चाहती है कि इस मुल्क में १०० फीसदी पढ़े-लिखे हो जायें ताकि वे अपनी नेकी और बदी को समझ सकें। तो यह मिस्टर चागला तसलीम करेंगे कि इस वक्त न सिर्फ टैक्नीकल कालेज में जगह नहीं है, और यूनिवर्सिटियां टैक्नीकल कालेज को अपना नहीं सकतीं चाहे वह इंजीनियरिंग कालेज हो, चाहे वह मैडिकल कालेज हो, चाहे वह एग्रीकल्चर कालेज हो इन के लिये यह भी मुश्किल है कि वह स्टूडेन्ट्स को जगह दें सके अपनी क्लासिज़ में तो ऐसी हालत में जब हम यह चाहते हैं कि हमारा मुल्क सारे का सारा पढा लिखा हो जाये तो हमें एक बिल ऐसा यूनिवर्सल बनाना चाहिये जिस में सारी यूनिवर्सिटियों के लिये एक सा रास्ता दिखाया जाये। सारे वाइस चान्सलर्स के लिये एक से रास्ते और हकूक मुकर्रर किये जायें। और यह क्या जरूरी है कि एक ही वाइस-चान्सलर को दूसरी बार भी मुकर्रर किया जाये। कोई बड़ा काबिल हो—चाहे डाक्टर राधाकृष्णन थे या मिस्टर चागला हैं—तो क्या कोई ऐतराज कर सकता है कि भाई इन से रिक्वेस्ट न की जाये। इन को फिर से इन्तखाब करने की शायद जरूरत ही महसूस न हो। इन्स्टीट्यूशन्स जो है, यूनिवर्सिटियां जो हैं या इन के अधिकारी जो हैं वे खुद-बखुद रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी रहनुमाई करें आप हमारी सेवा करें लेकिन यहां तो इस तरह से कोशिश की जाती है कि कुछ अधिकार अपने आदमियों को दिये जायें।

अगर कोई शिकवा न करे तो मैं कहूंगा कि अभी अभी फूलपुर में हमें शिकस्त हुई, और मैं इस को तसलीम करता हूं कि हमें शिकस्त हुई। लेकिन इस को भी तसलीम करता हूं कि वहां स्टूडेन्ट्स के ग़ौल के ग़ौल बाकायदा जत्थों की शक्ल में सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे और टीचर्स काम कर रहे थे। वहां कम्बल बंट रहे थे, वहां तरह तरह के कपड़े बंट रहे थे और परमिट बंट रहे थे।

श्री महाबीर प्रसाद भार्गव (उत्तर प्रदेश) : क्या ग़नी साहब का यह कहना है है कि आप के लिये काम नहीं कर रहे थे स्टूडेन्ट्स और टीचर्स ?

श्री अब्दुल ग़नी : पहले मैंने कहा था जब मैडम ने मुझे इजाजत दी थी, कि स्टूडेन्ट्स को जितना पलिटिक्स से बाज़ रखा जाये उतना ही देश के हित में होगा। मैंने यह नहीं कहा था कि वे अपोजीशन के लिये काम करें और सरकारी पार्टी के लिये काम न करें। जहां मिस्टर चागला यह चाहते हैं कि कोई भी इन्टीट्यूशन ट्रेनिंग के सिलसिले में कहिये,

[श्री अब्दुल गनी]

एजूकेशन के सिलसिले में कहिये, जो सरकार से बंधा हुआ नहीं है। जो अपने मनमानी तौर पर चलना है इस को ममनूह करार दिया जाये। मैं चाहता हूं कि कुछ यूनीवर्सिटियां ऐसी भी खोली जायें जिन के लिये इस तरह के नियम मुकर्रर किये जायें कि अगर २५ हजार की इजाजत दी तो २५ हजार ही खर्च हों, २५ लाख खर्च न हों। आप हमें शिकस्त दीजिए हमें शिकस्त से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन लाखों रुपया खर्च कर के फिर आकर यह कहना कि हम ने २५ दिये वह कोई माकूल बात नहीं है।

बहरहाल मैं यह कह रहा था कि एक यूनिवर्सल बिल आना चाहिए। सैलेक्ट कमेटी जो इस बिल पर बैठ रही है, इसके मुअज्जिज़ मेम्बरान और मिस्टर चागला से मैं यह अर्ज करूंगा कि कोई यूनिवर्सल बिल लायें और इस बात को न भूलें कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिस ने आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को दुनिया में फैलाया और रूहानियत की तरफ जिस का बड़ा रुख है। आज हमारी तालीम जिस ढंग से दी जाती है इस के सिलसिले में मैं यह कहूंगा कि मैं मैटर का मुखालिफ नहीं हूं। मैं यह नहीं कहता कि मादा कुछ भी नहीं हैं लेकिन मादा-परस्ती बुरी है। तो अगर इस तरफ हम अपनी एजूकेशन को ले जायेंगे तो मुझे खतरा है कि हमारे मुल्क की जो शान है और जो हजारहा बरस से हमारा देश सब का अगुवा रहा है वह बहुत पिछड़ जायेगा। मैं रिक्वैस्ट करता हूं कि जो भी सैलेक्ट कमेटी के मुअज्जिज़ मेम्बरान हों वे मेरी इस गुजारिश के बारे में भी विचार करें और विचार कर के फिर एक ऐसा रास्ता ढूंढें जिसमें हमारा मुल्क पिछड़ न जाये। आज हम सब यहां बैठे हुए हैं। आज लोक सभा बैठी हुई है। और मुझे डर है कि अगर सरकार इसी तरह से सब अख्तियारात को सिकोड़ती चली गई तो वह देश के लिये नुकसानदेह होगा। इन्हों ने अगर इन्डस्ट्री का कोई अख्त्यार लिया तो शायद किसी हद तक इन को दुनिया माफ करदे कि भाई नेशनलाइज़ करना था और काम नहीं चलता था पब्लिक सेक्टर के वगैर, इसलिये कुछ न कुछ किया गया। क्योंकि बाज़ इतने बड़े काम है कि इन को टाटा, बिड़ला और डालमिया और सिंघानिया सब मिल कर भी नहीं कर पाते। जब तक कि सरकार इन को अपने हाथ में न ले। टेक्नीकल इन्स्टीट्यूशन्स अगरचे कुछ लोगों ने या अच्छे आदमियों ने कायम किये है लेकिन अब यह साबित हो गया है कि वह भी अगर सारे अलग अलग चलते रहे तो नेशनल इन्टिग्रेशन का जो मकसद है वह शायद गस्ब हो जायेगा।

मुझे एक बात का यू० पी० में एहसास हुआ और मेरा यकीन है कि इस पर न सिर्फ मिस्टर चागला बल्कि हर अच्छे दिल के भाई—चाहे वह हिन्दु भाई हों, सिक्ख भाई हों, मुसलमान भाई हों, हरिजन भाई हों, ईसाई भाई हों—सब के सब विचार करेंगे। बद-किस्मती से या खुश-किस्मती से आज़ादी मिलने के पहले मुसलमानों की जितनी दीनी तालीम थी वह उर्दू रस्मुलखत में थी और मुसलमानों की जितनी पुरानी तारीख है जितनी इन की रवायात हैं चाहे वे हदीअत हो, शरीअत हो, सब के सब उर्दू रस्मुलखत में है। लेकिन अब वहां स्कूलों में उर्दू रस्मुलखत मिटा चाहती है, बल्कि मैं कहूंगा कि मिट गई है। तो ऐसी हालत में क्या चागला साहब ममनूह करार देंगे ? कैसे मुसलमान बच्चे ईमान को बनाएंगे ? वे भारत की तहज़ीब को, भारत के इतिहास को, भारत की सभ्यता को जहां सीखें वहां यह भी ज़रूरी है कि अपने दीन को भी सीखें और अपने दीन से बिलकुल लादीन न हो जाये। इसलिये अगर इसे ममनूह करार दें और यूनीवर्सिटीयों में या दूसरी जगह ऐसी फिज़ा पैदा की जाये तो फिर क्या

होगा ? कहते हैं कि दस बच्चे नहीं हों तो नहीं होगा । लेकिन मैं जहां गया वह सौ फीसदी मुसलमान गांव हैं फिर भी वहां उर्दू नहीं थी । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यूनीवर्सिटी बिल में से इसे . . .

श्री आबिद अली (महाराष्ट्र) : जनाब उर्दू को मुसलमान की ही ज़बान क्यों मान रहे है, वह बहुतों की है ।

श्री अब्दुल ग़नी : आबिद अली साहब, आप इसको मुसलमान की ज़बान कहें या हिन्दू की ज़बान कहें और मैं जानता हूं कि, इस में तिलोक चन्द मेहरूम, जगन्नाथ आज़ाद, फिराक और न मालूम कितने हैं । मै एक-एक का नाम नहीं लूंगा । लेकिन वाक्या यह है कि हिन्दुओं का इतिहास, हिन्दुओं की मज़हबी रवायात, हिन्दुओं का मज़हब व दीन देवनागरी में है और मुसलमानों का मजहब मुसलमान की रवायत, मुसलमानों का इतिहास, मुसलमानों का दीन नब्बे फीसदी उर्दू रस्मुलखत में है। यह एक हकीकत है जिसको छिपा नहीं सकते । मेरा अर्ज़ करना यह था । मैं यह नहीं कहता कि कोई बड़ी अफरातफरी की इजाजत दें, कोई बेचैनी कायम करें इसके हक में मैं नहीं हूं लेकिन जहां मजबूरी है इसके लिये कोई रास्ता निकाला जाये यह भी देखना है । तो कोई न कोई रास्ता इस देश वालों को निकालना पड़ेगा क्योंकि हिन्दू बड़ा भाई है और मुसलमान छोटा भाई है । इसे छोटे भाई के लिये देखना पड़ेगा कि आया इसके रास्ते में कोई अड़चन तो नहीं आती है और अगर आती है तो सैलेक्ट कमेटी को इस पर भी कुछ विचार करना चाहिए ।

अब रहा यह सवाल जो कि चौरड़िया जी ने उठाया कि आप यहां और सिकोड़ना चाहते हैं ५० लाख की बजाए ४५ लाख करना चाहते है । मै ४५ लाख और ५० लाख के झगड़े में नहीं पड़ता, मैं तो इस स्पिरिट के खिलाफ़ हूं । अगर वाकई आप यूनीवर्सिटियों को मजबूत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यूनीवर्सिटियां देश के काम आयें, देश की ऐन मन्शा के मुताबिक चलें और इस में वही बात चले जो कि सरकार चाहती है—चाहे यहां कोई सरकार बैठी हो, चाहे वह सोशलिस्ट हों, चाहे वह हमारे शास्त्री जी हों उनकी जो ख्वाहिशात हैं और जिस तरह वह मुल्क को प्लान करके आगे चलाना चाहते हैं यूनिवर्सिटियां इन का बाइस बनें—तो मैं मानता हूं कि इन को ज़रूर कुछ रास्ता निकालना चाहिए । वे जो रास्ता निकालना चाहते हैं उस में मैं इनके साथ हूं लेकिन इस के साथ यह भी चाहता हू कि वे देखें कि मुल्क के लोग जो यहां बसे हैं इनके लिये क्या ठीक है । मिस्टर चागला शायद इसको बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं कहूं कि आज यूनिवर्सिटियों से पास हुये किसी एम० ए० को ले लीजिए और उससे पूछिए कि अपने यहां गंदम, अपने यहां बीज, कितना होता है तो वह बता नहीं पायेगा । देश का जो हित है, देश की जो समस्या है, इस को वे साहेबान नहीं बता पाते । वह क्यों नहीं बता पाते । इसलिये कि हमारे यहां दुनियां के बाकी मुल्कों के मुकाबले में इस तरह से स्टूडेंट्स को तालीम दी जाती है कि हमारे यहां में और उन के यहां में बहुत फर्क है । वे क्यों जनरल नोलिज में इतने होशियार होते हैं ? क्यों वे अपने मुल्क की हर मुश्किल को, हर अड़चन को, हर दिक्कत को जानते हैं ? अगर कोई भाई बुरा न माने तो मैं कहूंगा कि सिवाय रफी साहब के जो कि हरफन मौला थे और कोई नहीं हैं कि किसी मजमून पर खड़ा कर दिया जाये और बोलने के लिये कह दिया जाये । उन्होंने अगर डाकखाना को सम्भाला, कम्युनिकेशन को सम्भाला तो इतना सम्भाला कि दुनिया याद करती है । फूड पर आये तो इतना सम्भाला कि दुनिया याद करती है । लेकिन आज हर मिनिस्टर के लिये यह मुश्किल है कि हरफन मौला हो । तो हम ऐसा स्टेंडर्ड यूनीवर्सिटियों का बना सकें

[श्री अबदुल ग़नी]

जिसमें कि लड़के जहां एक क्लर्क बनने की सलाहियत हासिल करें वहां लड़के आफिसर बनने की सलाहयित भी हासिल करें । वह मुल्क के सब से बड़े सेवक हों, मुल्क के सब से बड़े सिपाही हों, मुल्क के सब से बड़े लीडर हों, उनमें इतनी सलाहियत पैदा की जाये ।

तो मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि चागला साहब से मुझे न सिर्फ मौहब्बत है बल्कि इन से मुझे अकीदत भी है । वह मुल्क के काबिलतरीन नेताओं में हैं वह चाहे कांग्रेस में हों या जज रहे हों, कहीं भी रहे हों उन्होंने अपनी काबिलियत का सिक्का जमाया है और मुझे उम्मीद है कि वह मेरी दरख्वास्तों पर तवज्जो देंगे और यूनीवर्सिटियों में फिर से ऐसी शान पैदा करेंगे कि इन की डिग्रियां चीप न हों और चीप लीडरशिप के लिये डिग्रियां न दी जायें । यह मैं इसलिये कहता हूं कि हमें इन की शान को कायम रखना है । मुझे यकीन है कि वह मेरी बातों पर तवज्जो देंगे ।

मैडम डिप्टी चेयरमैन साहिबा, मैं आपका बहुत ममनूह हूं कि आपने मुझे इतना मौका दिया । मैंने जनरल बहस की बजाय इसके कि एक-एक धारा पर बहस करता । वह बहस तो सिर्फ कमेटी में होगी और जब सैलेक्ट कमेटी के बाद यह बिल आयगा तब वक्त आयेगा कि इसकी एक-एक धारा पर कुछ अर्ज करूं, इस में कुछ आप की मदद कर सकूं और कुछ तरमीम पेश कर सकूं । इस वक्त तो मुझे जनरल तौर पर यह देखना है कि यह बिल जो लाया गया है इसको बदलाना चाहिए या नही इस की स्पिरिट को बदलना चाहिए या नही और किस तरह से इसे एक यूनीवर्सल बिल बनाना चाहिए ताकि एक ही बिल सारी यूनीवर्सिटियों पर लागू हो और मुल्क में जो इस वक्त कमी आ गई है वह दूर हो । जो हम बच्चों को जगह नहीं दे पाते, हम बच्चों की पूरी तरह हिफाजत नही कर पाते, हम बच्चों की पूरी मदद नही कर पाते, हम इनको पूरे वजीफ नही दे पाते, हम इनको बाहर के मुल्कों में भेज नहीं पाते, इन सब में आसानी पैदा हो । खुदा करे, चागला साहब यहां रहें । कांग्रेस सरकार यहां रहे वह जुग जुग जिये । इस का हमें दुःख नहीं है कि वह फूलपुर में जीते या कहीं जीते वह जीते और जिये । लेकिन यह मैं जरूर चाहता हूं कि मेरी जो दरख्वास्तें हैं इन पर तवज्जो दी जाये । आपका शुक्रिया ।]

SHRI M. C. CHAGLA: Madam Deputy Chairman, may I express my gratitude to the Members of the House who have participated in this debate and for making some very valuable suggestions, which, I am sure, will be duly considered in the Select Committee?

Now, my friend, Mr. Ghani, the last speaker in the debate, said that we should have a comprehensive Bill which would apply to all the Universities. I am sure he knows the constitutional position. 'Universities' are a State subject and we have no right to legislate on State Universities. Our right is confined to legislate on Central Universities and as Banaras is a Central University, we can pass legislation with regard to that University. When 'Universities' become a Concurrent subject, which I hope some day it will be, then certainly it will be our duty to have a comprehensive legislation affecting all the Universities.

Now, a great deal was said about a Committee appointed by the University Grants Commission, which has been known as the Model University Bill Committee, and I think one or two of my hon. friends asked me: Why was this Bill introduced before that Committee had made its report and why did we not have the Bill framed in accordance with the views taken by that Committee? Now, I waited for a long time before introducing this Bill. I wanted the report of the Committee, but the Committee dragged on its proceedings and even

to-day their report is not before us. But I assure the House that I was in constant touch with Dr. Kothari, who is the Chairman of the University Grants Commission. I know his thinking with regard to model Bills. The Bill was drafted after we knew on what lines Members of the Committee were thinking. Therefore, when you get the report of the Model University Bill Committee, you will find that this Bill does not materially differ from the recommendations of that Committee.

Now, coming to some of the more specific criticisms and comments, may I first turn to my friend, Thakur Niranjan Singh? He has raised the question as to why the Vice-Chancellor's term of office should be five years when the Chancellor's term of office is three years. The answer is very simple. The Chancellor's office is a formal office. He discharges hardly any functions. I think the function he discharges is to preside over the Court; whereas the Vice-Chancellor is the heart and soul of the university and unless he has a fairly long period of office he cannot achieve anything. He cannot mould the policies of the university, make important changes, lay down programmes or policies. Therefore, five years in my opinion is the minimum period for which the Vice-Chancellor should be appointed.

My friend, Mr. Chordia, made two comments about the appointment of the Vice-Chancellor which, unless I misunderstood him, seem to me rather inconsistent. He is a very able and careful speaker; perhaps the mistake is mine. He first mentioned why the term of office of the Vice-Chancellor is fixed at two terms, why he could not be appointed for a third term if he was found to be fit.

SHRI V. M. CHORDIA: That was my question. What was your object behind keeping this provision in the Bill?

SHRI M. C. CHAGLA: The object is this. If a Vice-Chancellor gets two terms, he remains Vice-Chancellor for ten years which we thought was long enough for any one. After ten years a man is liable to get stale, and you want a man with a fresh outlook.

شری عبدالغنی : مسٹر چھاگلا یہاں تو اٹھارہ اٹھارہ برس مسٹر رہے -

†[श्री अब्दुल ग़नी : मिस्टर चागला, यहा तो अठारह-अठारह बरस मिनिस्टर रहे ।]

SHRI M. C. CHAGLA: I assure my hon. friend that that will not happen in my case. That was the reason why we thought we should not extend it to the third term.

Then a point was made by my friend, Mr. Chordia, quoting from the Radhakrishnan Report, that the Vice-Chancellor should be appointed for one term and there should be no question of his reappointment because, if there is a possibility of his being re-elected or re-appointed, he works with an eye to his constituency or to his voters or to the chance of his being re-elected. The system that we have provided in this Bill will prevent any canvassing on the part of the Vice-Chancellor. Of course, as you know, the scheme is that the Executive Council appoints a Committee of two and one is appointed by the Visitor, and this Committee appoints a panel of three and from that panel the President selects the Vice-Chancellor. The President is not bound by this panel. He may reject all the three and ask for fresh nominations. I do feel that the Vice-Chancellor of a university either makes the university or mars the university, and therefore nothing is more important than the appointment of a proper and suitable Vice-Chancellor. I also agree that in the 61 universities we have in this country, with all respect, every Vice-Chancellor who has been

†[ ] Hindi transliteration.

[Shri M. C. Chagla.]

appointed is not a suitable Vice-Chancellor, and I have been seriously thinking whether we cannot persuade the States to pass legislation by which Vice-Chancellors of all State universities will be appointed by the Centre. Then we will have some uniformity. We will have appointments made which will not be subject to party pressures or political pressures, and when this report of the Model Bill Committee comes before me, I will circulate it to all the States so that they can draft legislation on the lines of this report.

Then a point was made by my friend, Mr. Niranjan Singh, as to why the Court, which is described as the supreme authority, should not have powers over day-to-day administration. If you remember, Madam, the whole trouble, which arose in the Banaras University which necessitated an Enquiry Committee and the passing of an Ordinance, was that the Court interfered too much. A large body like that subject to all types of pressures and elected from various sources is not a body which is intended to deal with the day-to-day administration, and it is because of this that we have left the day-to-day administration to the Executive Council. But the Court has supervision over it, but only to the extent of supervision. If the Court were to interfere with administration, there will be chaos in the University.

Then the other point made by my friend was, why it is proposed that the Treasurer should not be appointed from amongst the employees of the university as the Registrar can be. The intention is that the Treasurer should be a person who should have knowledge of finance and he should be a senior officer from the Indian Audit and Accounts Service. Again it was with regard to the post of Treasurer that we had a great deal of trouble in the Banaras University on the last occasion. So we want a man from outside who has nothing to do with the administration of the university and is not recruited from the office of the university. He should be somebody from the Finance Department or the Audit Department so that he should be able to look after the finances of the university.

Turning to my friend, Mr. Mani, he made a point—I am afarid, not with much justification—that we have made a deliberate provision for the continuance of a Vice-Chancellor or a Treasurer for a period of one year if his successor has not been appointed. I assure my hon. friend—he knows me well enough to accept my assurance—that there was no personal consideration in making this suggestion. It was an ordinary provision that there should be no interregnum between the appointment of one Vice-Chancellor and the other. But I assure my hon. friend that we will think far ahead and before the term of a particular Vice-Chancellor comes to an end, we shall have the next incumbent in mind and he will be appointed immediately. But it is purely for administrative reasons that this provision has been made.

I am afraid that Mr. Mani also suggested that we should be more careful about conferment of the honorary degrees of Doctorate. I entirely agree. My own university, the Bombay University, in its hundred years of history has hardly conferred three or four Doctorates and that too to most eminent people in India. I want other universities to follow that example. But after all we cannot interfere with the autonomy of the university. It is for the university to decide where eminence lies and find it. But I will certainly consider the formula suggested by Mr. Mani that we should restrict this honour to persons who have worked for the public good. That is a very wide expression, a very good expression, and I will certainly see how the Select Committee reacts to that instead of laying down different categories. But may I point out that Mr. Mani had some caustic remarks to make about conferring degrees on

statesmen? The Bill does not say that degrees should be conferred upon politicians. It says that it should be conferred upon statesmen, and Mr. Mani has sufficient experience to know the difference between a politician and a statesman.

Then Mr. Mani has made a very good suggestion about clause 5(a)(2) that it should be amended as to read "to promote Oriental studies in theology, religion and culture" in place of "to promote Oriental studies including Vedic, Hindu, Buddhist and Jain studies, to give instruction in Hindu theology and religion and in moral and spiritual values and to impart physical training". Personally, I am all for it. I think every university, if it wants to have a Department of Religion, it should study comparative religion, it should study Indian culture and our different religions constitute Indian culture. If the House is favourable to this amendment, I will certainly personally support it and I shall also see to it that a similar amendment is made in the Aligarh Muslim University Act which has also got similar language.

3 P.M.

Some hon. Member suggested—I think it was my hon. friend from Orissa—that this was the time to delete from the title of this Bill the expression 'Hindu'. Again, if this is the feeling of the majority of the House, I shall welcome it and I will also give an assurance to this House that I will immediately introduce an amending Bill to the Aligarh Muslim University Act to remove the word 'Muslim' from the Aligarh University.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): But as I said to the Education Minister, a more substantial thing will be that both these universities should have at least one third of the students and staff from the other community and I hope that in this Act and the Aligarh University Act the Education Minister will do it.

SHRI M. C. CHAGLA: I agree. That is why I said it in my opening remarks that what matters is not the nomenclature, what matters is the spirit in which an institution is worked. You may call a university 'Hindu University' and yet you may work it in a national, not communal, spirit. You may call the Aligarh University, the 'Aligarh Muslim University' and you may yet work it in a national, not communal, spirit. But if the very name emphasises communalism, as I said, if the general sentiment of the House is that this is the time to change the name of this University, I shall support any such amendment and as I said, I will certainly introduce an amendment to the Aligarh Muslim University Act to the same effect.

With regard to the suggestion of my hon. friend, Mr. Akbar Ali Khan, I agree that it would be a very happy thing if in the Banaras University you had a certain percentage of students of the other communities; equally so, in the Aligarh University.

Then, Mr. Ghani wanted to know why it is proposed to give to the Vice-Chancellor sweeping disciplinary powers like expulsion of students when such a provision does not exist in the Acts of the other Central universities. Well, we know what happened in the Banaras University and if discipline is to be enforced, power must be given to the Vice-Chancellor.

I think Mr. Ghani talked of dictatorship but if you look at the provision of the Bill, it provides that:

> "no student shall be expelled unless a charge-sheet is framed against him and he has been given opportunity to show cause against the accusation made against him."

Therefore it is not dictatorship, but it is the working of the rule of law. If we want to enforce discipline, we must give power to someone to enforce it and after all, if we cannot trust our Vice-Chancellors, well, then there is the end of higher education.

[Shri M. C. Chagla.]

Appoint good Vice-Chancellors, appoint proper Vice-Chancellors and then invest them with all the authority necessary to enforce discipline.

شری عبدالغفی : انسان انسان ہے اور انسان بھول سکتا ہے وائس چانسلر بھی انسان ہے اس لئے اسٹوڈنٹوں کو اپیل کرنے کا حق ہونا چاہیئے اور ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیئے -

†[श्री अब्दुल गनी : इन्सान इन्सान है और इन्सान भूल कर सकता है। वाईस चांसलर भी इन्सान है इसलिए स्टुडेन्टों को अपील करने का हक होना चाहिये और उनके साथ इन्साफ होना चाहिये।]

SHRI M. C. CHAGLA: Well, I will certainly consider whether there should be a right of appeal against the decision of the Vice-Chancellor. I will consider it in the Select Committee.

Then I come to my friend, Mr. Bhupesh Gupta. He is not here. I think it was more a very interesting discourse on general education than on the Banaras Hindu University Bill as such.

Then we have our friend, Shri Chandra Shekhar. He referred to the point which I have already referred to, as to why the Bill was brought up before the promised model Act for the universities was ready. Then he asked why representation is not given to the teachers. This is not right. There are 27 representatives of teachers on the Court of the University in the Bill. And on the Executive Council there are three Deans of Colleges in addition to the Dean of Students and the Principal, Women's College. So the teachers have been sufficiently represented.

†[ ] Hindi transliteration.

During the debate this morning, I think my friend, Mr. Chordia, made the point as to why the University should be asked to approach the Government for any amount that it might have to borrow. Now, we have had a very bad experience in the past. The University spent recklessly, borrowed monies as it liked and we felt that we should have some control over it. Now, do not forget that we pay every anna not only of the developmental expenses but also the maintenance expenses on the Central universities. So, normally there is no reason why the University should borrow money at all. If the expenditure is legitimate, we will pay for it. They should come to us and say, we want money for this. But to give them authority to borrow money without the sanction of the Government would lead to financial bankruptcy.

Then he made the point: why should the Vice-Chancellor not be appointed by the University authorities instead of by the Visitor. Now, we do not want the appointment of the Vice-Chancellor to become the happy hunting ground for politics and canvassing. In a large Court, if the Court is to appoint, well, there will be canvassing. If the Executive Council is to appoint—which is a smaller body—there will be canvassing. Here we have reduced it to a system which has worked very well in other Central universities. That is the scheme in the Delhi University, that is the scheme in the Aligarh University and I think on the whole this is the only system we can think of which will, as far as possible, eliminate canvassing.

Then, Mr. Chordia made a point which, I am afraid, he did without realising the implication of the amendment. And the point was: why should the amount of Rs. 50 lakhs be reduced to Rs. 45 lakhs? His view seems to be that this refers to recurring expenditure. It does not. This is an endowment which was made by grants from the Bikaner Durbar and the Kashmir Durbar. And already

there is a deficit of Rs. 4·15 lakhs in this Endowment Fund. The University has used it and therefore to bring it nearer to reality we are reducing this Endowment Fund to Rs. 45 lakhs instead of Rs. 50 lakhs. If my hon. friend will look at the original section in the Act which is section 14, it says:

> "The University shall invest, and keep invested in securities in which trust funds may be invested, in accordance with the provisions of the law relating to trusts in India, a sum of fifty lakhs of rupees as a permanent endowment to meet the recurring charges of the University other than the charges in respect of scholarships, prizes and rewards:"

That means that they can only use the interest and the endowment has to be kept. Now, what has happened is that the University has already utilised Rs. 4·15 lakhs out of this Endowment Fund. They should not have done so.

SHRI V. M. CHORDIA: Ther regularise it. We want it should be done.

SHRI M. C. CHAGLA: You want us to make a present of Rs. 4·15 lakhs? My hon. friend will realise that after all, we are liable for recurring and non-recurring expenses. Even if the interest realised is not sufficient, the Government undertakes full liability with regard to the Banaras University.

Then my friend, Mr. Chordia made a point as to why conviction for moral turpitude is not a permanent disqualification. I think there is force in this point; there is force in what he says. A man who is an educator, a man who is to be moulding the destinies of young men and women, if he is guilty of moral turpitude, he should not be placed in that highly responsible position. But we consulted the Ministry of Law on this point and it was pointed out to us that even under the Representation of the People Act, 1951, conviction for any offence is a disqualification only for a period of five years from the expiry of the sentence and not for all times. So we felt that if a Member of Parliament can come back to Parliament after having been convicted . . .

SHRI V. M. CHORDIA: We cannot keep them at par.

SHRI AKBAR ALI KHAN: But not the University people.

SHRI M. C. CHAGLA: I do not like to put professors of Universities at par. I certainly put Members of Parliament on a higher pedestal. I have much respect for them.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : यूं तो सूरदास पहले क्या थे और बाद में क्या हो गये और तुलसीदास पहले क्या थे और बाद में क्या हो गये, यह ठीक है, मगर इसकी व्यवस्था तो हम वैसी नहीं करना चाहते ।

SHRI M. C. CHAGLA: We will certainly consider this in the Select Committee.

Then Mr. Chordia has mentioned about the powers of the Visitor. And one of the points he has made is about the disallowance of ordinances. Now if you look at the scheme of the Bill, an ordinance is passed by the Executive Council. Then it comes to the Court and the Court has a right to disallow it, I think, by a two-thirds majority. If the Court allows it, it comes to the Visitor and the Visitor has been given the power to disallow it within a certain time. Now it is very necessary to have all these checks. You know the Visitor is guided by the Central Ministry, and it is not likely that the Visitor would disallow an ordinance which has been passed by the Executive Council and approved by the Court unless there is very strong reason to do so. I want to assure my friend, I am a great believer in autonomy of Universities. I think scholarship can only flourish in academic freedom and I will be extremely loath to interfere with the

[Shri M. C. Chagla.]

working of Universities. But looking at the things going on, some control has got to be kept. These powers are reserve powers. They will rarely be used but we must have the power in case somebody runs amuck and passes an ordinance which might bring about an impossible situation.

Now sub-clause (7) of clause 7E on page 7 points out:

> "If, in the opinion of the Vice-Chancellor, any emergency has arisen which requires immediate action to be taken, the Vice-Chancellor shall take such action as he deems necessary and shall report the same for approval at the next meeting to the authority which, in the ordinary course, would have dealt with the matter:
>
> Provided that, if the action taken by the Vice-Chancellor is not approved by the authority concerned, he may refer the matter to the Visitor, whose decision thereon shall be final:"

And I think a justifiable criticism was made that what happens to the action already taken by the Vice-Chancellor. I think we might have to provide that actions taken should be validated although there may not be approval, or some such provision will have to be made. The Select Committee will consider that suggestion.

Then, Madam, Mr. Chordia said that more power should be given to the Court. Now we carefully considered this. If he looks at the Mudaliar Committee Report, he will find that most of the trouble was due to what the Court did. Therefore, except making it a supervisory body, a supreme body, a body that lays down the policy, it would be a great mistake in my opinion to give it any more powers than what we have given.

SHRI NIRANJAN SINGH (Madhya Pradesh): May I know, Madam why trouble was given by the Court to the Executive Council or the Vice-Chancellor? After all, they are a superior body and, therefore, their order has got to be obeyed by the Executive Council rather than the Court obeying the order. Hence the trouble.

SHRI M. C. CHAGLA: Trouble was given because Court was a large body; it was an elected body. There are factions and groups. These got into the Court also. There were parties. There were differences of opinion and the working became impossible. So the Mudaliar Committee said, "Well, cut down the body". As a matter of fact, the Mudaliar Committee went much farther than we have done. Therefore, we have restricted the power as much as possible. We felt that to leave the power only to the Vice-Chancellor and the Executive Council would not be democratic. And, therefore, there should be a higher body which should supervise, who should lay down the policy.

SHRI NIRANJAN SINGH: You are giving the power of supervision to the Court.

SHRI M. C. CHAGLA: I am not. If you look at the Bill, we have given them the power. We say it is a supreme body.

SHRI NIRANJAN SINGH: That is the thing. You have curtailed the power of the Court.

SHRI M. C. CHAGLA: Supervising in the sense that it can call to order, as it were, the Executive Council if it goes wrong. It can criticise the Executive Council. It can tell them that this is wrong. It can tell them that you must follow this policy. But it will not meet every week or every fortnight. It will meet once or twice in a year. It will have general discussion, as you have, for instance, in the Bombay University which I know very well. You have got there a Senate, a large body, which is like a

Court. They used to meet twice or thrice a year. The syndicate used to meet almost every week. That is exactly what we are doing here.

SHRI AKBAR ALI KHAN: The first is deliberative while the other is administrative.

SHRI M. C. CHAGLA: Then Mr. Chordia referred to the provision in the Bill about restricting the Banaras Hindu University from affiliating any colleges other than those already affiliated to it. He wanted to know the objection for doing so. According to him, if new colleges spring up within the area why should the Banaras Hindu University be restricted from affiliating those colleges? The answer is this. The Banaras University was intended to be a unitary, residential, teaching university; it is not an affiliating university.

SHRI V. M. CHORDIA: But in spite of that they have affiliated some colleges.

SHRI M. C. CHAGLA: The reason for affiliating those colleges is historical. When Malaviyaji formed this University, some colleges were there. He wanted the colleges to remain in the Banaras University. And as my hon. friend Mr. Chordia, knows there is even a school which forms part of the University. These are the historical reasons. But Malaviyaj's idea in founding this University was essentially that of a residential, unitary, teaching university. And we want to keep that complexion. Once you give the University the right to affiliate colleges, it will become like any other University, like the Calcutta University with hundreds of colleges affiliated to it. The whole character of the University will change. And I think the greatness of the Banaras University and the Aligarh University, to my mind, is that both are residential, unitary, teaching universities. Now, no hardship arises by not giving the University the right to affiliate colleges. If it wants to start a new faculty, it can start a University department. If it wants to have more students, it can expand the University department. Why have a college? The idea is that the control of teaching should be only with the University. I wish all our universities were unitary teaching universities but history has developed in a different way. We started with affiliated colleges, not teaching universities. Bombay was the same, Madras was the same and Calcutta was the same. They just affiliated colleges and the colleges did the teaching. It is only recently that the Bombay University has got a Teaching Department. But Banaras and Aligarh which started later had different ideas and we must remain true to those principles. I think they are sound principles.

Then my friend, Mr. Sankar Pratap—I believe that is my friend from Orissa—suggested—it is a very good suggestion—that we should have guardian committees to advise the university authorities. You might call them guardian committees or parent associations but these must be formed on a voluntary basis. You cannot have a statutory provision for it. I wish in this country there were more organisations like this who would look after institutions, go and advise the authorities what is wrong with them. It will have a very good, salutory control over the educational authorities. I am sure my friend from Orissa will try to build up such organisations. It will do a lot of good.

I think, to the best of my recollection I have dealt with almost all the points raised in the debate and I express once more my gratitude to the Members who have participated in it and I assure them that all the points will be taken into consideration when the Bill comes before the Select Committee.

Thank you.

SHRI N. M. ANWAR (Madras): On a point of clarification. Madam, I have

[Shri N. M. Anwar.]

got the highest respect for the hon. Minister, Mr. Chagla's accumulated treasures of mature experience and wisdom too but I was surprised, indeed flabbergasted, when he said that in our country he will come forward with a proposal to drop the denominational character of the Hindu University and the Muslim University.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is the clarification you need about it?

SHRI N. M. ANWAR: I am coming to it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has left it to the opinion of the House.

SHRI N. M. ANWAR: He made a very dangerous observation fraught with potentialities for mistrust and mischief when he said that nomenclature or denominational name of a particular community rather makes the institution communal. I must say that there are thousands of institutions in our country run by different denominations—the Hindu schools and colleges as well as university, the Muslim schools and colleges as well as university, the Christian schools and colleges, the Khalsa schools and colleges, etc.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not know what you want to say. Come to the point.

SHRI N. M. ANWAR: I am coming to the point. I am saying that once you try to give the impression that because of their denominational character they are communal, I am afraid there is no end to the mischief. Indeed, the Minister was introduced in the United Nations as Mr. Mahomedali Currim Chagla, as the finest proof of our secular State.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think you have not really any point for clarification.

SHRI N. M. ANWAR: I have a very serious point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I cannot give you more time. Your point is made clear. Mr. Chagla has only thrown a suggestion. It is for the House to accept. It is going to the Select Committee and, I think, it will be cleared there.

SHRI M. C. CHAGLA: I do not want the House to have any misunderstanding. I think my hon. friend misunderstood me. He has put in my mouth something contrary to what I said. I said explicitly that what matters is, what goes on inside an institution and not the name. I said that.

SHRI N. M. ANWAR: I am glad. I am now satisfied with this clarification.

SHRI M. C. CHAGLA: I said it. Perhaps the hon. Member was not here. I said if the House wants it, if the majority of the House wants the name to be changed, I am for it, but what I want is that the instituiton itself should be national—name does not matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think you are satisfied now.

The question is:

"That the Bill further to amend the Banaras Hindu University Act, 1915, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 45 Members; 15 Members from this House, namely:

1. Shri Jairamdas Daulatram.
2. Shri P. K. Kumaran
3. Prof. Mukut Behari Lal
4. Shri Tarkeshwar Pande
5. Dr. B. N. Prasad
6. Dr. Nihar Ranjan Ray
7. Shri N. Narotham Reddy
8. Shri M. Ruthnaswamy
9. Shri P. N. Sapru
10. Shrimati Sharda Bhargava
11. Shri R. P. N. Sinha
12. Shri Dattopant Thengari

13. Shri S. K. Vaishampayen

14. Prof. A. R. Wadia

15. Shri M. C. Chagla (the mover);

and 30 Members from the Lok Sabha;

that in order to constitute a meeting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Select Committees shall apply with such variations and modifications as the Chairman may make;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session; and

that this House recommends to the Lok Sabha that the Lok Sabha do join in the said Joint Committee and communicate to this House the names of Members to be appointed by the Lok Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

THE REPEALING AND AMENDING BILL, 1964

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI JAGANATH RAO): Madam, on behalf of Mr. A. K. Sen, I beg to move:

"That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments be taken into consideration."

This Bill is a purely formal measure and the reasons for sponsoring the Bill are set out in the Statement of Objects and Reasons appended to the Bill. The enactments that are sought to be repealed are mentioned in Schedule I annexed to the Bill. These enactments have ceased to be in operation or they have become unnecessary. The enactments which are sought to be amended are appended in the Second Schedule to the Bill.

[THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE) in the Chair].

These amendments are purely formal in nature and are aimed at correcting technical errors or defects. The notes on clauses appended to the Bill mentions the reasons why certain enactments are sought to be repealed and the reasons why certain amendments are sought to be introduced to the Acts appended in Schedule II. This is one of the formal routine measures introduced periodically. The last Repealing and Amending Act was passed in 1960 and this Bill seeks to repeal certain enactments enumerated in Schedule I and amend certain enactments which are enumerated in Schedule II, and the whole idea is to bring the Statute Book up-to-date and remove from the Statute Book enactments which have ceased to operate and whose continuance is considered unnecessary. This opportunity is availed of to introduce certain amendments which are purely of a formal or technical nature. As I submitted, this measure is of a very non-controversial and formal nature and I commend this motion for the acceptance of the House. I move.

The question was proposed.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, यह बिल जो प्रस्तुत किया गया है इसमें कुछ कानूनों को रिपील किया गया है और कुछ में संशोधन किया गया है। इन संशोधन किए गए कानूनों की यादी में अभी हाल ही में १९६१ में, १९६२ में और १९६३ में जो कानून बने वे भी हैं और उनमें भी संशोधन चाहा है। वे संशोधन कोई ऐसे बड़े नहीं है कि कोई विशेष आपत्ति हो, शाब्दिक गल्ती होने की वजह से उनको ठीक करने की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से ठीक करने के लिए वे लाए गए है। लेकिन मेरा एक नम्र निवेदन है कि यह कानून का प्रश्न इतने महत्व का है कि यदि इसमें हम थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो उसका सारे देश पर बड़ा भारी असर पड़ता है।